

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 5 • कठुआ, शनिवार 31 जनवरी 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

सीतारमण द्वारा लगातार 9 बजट पेश करना गर्व की बात है : पीएम मोदी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किए जाने को भारत के संसदीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण और गौरवपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि न केवल व्यक्तिगत स्तर पर ऐतिहासिक है, बल्कि देश की लोकतांत्रिक परंपराओं और निरंतरता को भी रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री के अनुसार, बजट प्रस्तुति की यह निरंतरता शासन में स्थिरता, नीतिगत स्पष्टता और आर्थिक सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जो लगातार नौवीं बार संसद में बजट पेश करने जा रही हैं। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र और संसदीय



इतिहास में एक उल्लेखनीय अध्याय करार दिया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि बजट केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होता, बल्कि यह देश की आर्थिक

दिशा, प्राथमिकताओं और भविष्य की विकास यात्रा का प्रतिबिंब होता है। प्रधानमंत्री के बयान के साथ ही यह तथ्य भी सामने आया कि भारतीय संसदीय

इतिहास में इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने कुल 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था। हालांकि, ये बजट लगातार वर्षों में प्रस्तुत नहीं किए गए थे। इसी तरह, पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने भी नौ बार बजट पेश किया, लेकिन वह भी निरंतर वर्षों की श्रृंखला नहीं थी। इस दृष्टि से देखा जाए तो निर्मला सीतारमण का लगातार नौ वर्षों तक बजट प्रस्तुत करना अपने आप में एक अनोखी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी संकेत दिया कि आने वाला बजट देश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि बजट में समावेशी विकास, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे के विस्तार, तकनीकी नवाचार और सामाजिक कल्याण से जुड़े उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के अनुसार, बीते वर्षों में सरकार ने आर्थिक सुधारों, डिजिटल परिवर्तन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं, और आगामी बजट इन प्रयासों को

■ शेष पेज 2...

नागरिक सचिव अटल दुल्लू ने डिजिटल कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : मुख्य सचिव अटल दुल्लू ने आज जम्मू-कश्मीर में कार्यान्वित की जा रही प्रमुख डिजिटल अवसंरचना पहलों, जिनमें 4जी संतृप्ति परियोजना, संशोधित भारतनेट कार्यक्रम (एबीपी), 5जी तत्परता, कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) और अन्य संबद्ध दूरसंचार परियोजनाएं शामिल हैं, की स्थिति की समीक्षा के लिए 10वीं राज्य ब्रॉडबैंड

समिति (एसबीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में पीडब्लू के एसीएस, वन आयुक्त सचिव, जम्मू-कश्मीर के एलएसए के डीडीजी, सूचना सचिव, आरडीडी सचिव, बीएसएनएल के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उपायुक्तों ने अपने-अपने कार्यालयों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।

इस बैठक के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी सचिव डॉ. पीयूष सिंगला ने अक्टूबर में आयोजित पिछली एसबीसी बैठक के बाद से हुई क्रमिक प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी। मुख्य सचिव ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई निरंतर प्रगति का संज्ञान लिया और सभी स्वीकृत स्थलों के समय पर पूरा होने को सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन समयसीमा में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

4जी सेचुरेशन प्रोजेक्ट की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव को सूचित किया गया कि 775 मोबा. इल टावर स्थलों के लिए कार्य आदेश जारी किए गए हैं। इनका उद्देश्य सीमावर्ती, पहाड़ी और सुदूर क्षेत्रों में स्थित उन गांवों को

■ शेष पेज 2...

मुख्यमंत्री ने सांबा में 10 एमवीए रिसीविंग स्टेशन की आधारशिला रखी, ठंडी खुई में बस टर्मिनल का उद्घाटन किया

सबका जम्मू कश्मीर

सांबा : मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज सांबा जिले का दौरा किया और हरमिंदर में 10 एमवीएसी रिसीविंग स्टेशन की आधारशिला रखी। उन्होंने विजयपुर के ठंडी खुई स्थित बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया।

सांबा के हरमिंदर में रिसीविंग स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्थानीय लोगों से बातचीत करते हुए कहा कि हरमिंदर में 10 एमवीएसी रिसीविंग स्टेशन की आधारशिला सांबा, विशेष रूप से इस क्षेत्र में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और वोल्टेज स्थिरता में सुधार लाने के एकमात्र उद्देश्य से रखी गई है। उन्होंने कहा कि एक बार चालू होने के बाद, रिसीविंग



स्टेशन मौजूदा बुनियादी ढांचे पर भार कम करेगा और घरों, किसानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए अधिक विश्वसनीय और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। किसानों को जम्मू-कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा

कि जिस प्रकार सीमा पर सैनिक हमें शत्रुओं से बचाते हैं, उसी प्रकार किसान हमें भूख से बचाते हैं। उन्होंने कहा कि सैनिकों और किसानों दोनों को समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता है, और सरकार उनके कल्याण और भलाई के लिए प्रतिबद्ध है।

■ शेष पेज 2...

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची की तार्किक विसंगतियों की सूची में शामिल नामों को प्रदर्शित करने का निर्देश दिया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि विभिन्न राज्यों में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन के दौरान, ग्राम पंचायत भवनों और ब्लॉक कार्यालयों में पार्षदिक विसंगतियों की सूची में शामिल लोगों के नाम प्रदर्शित किए जाएं, जहां दस्तावेज और आपत्तियां भी प्रस्तुत की जाएंगी।

बिहार में संशोधन पूरा होने के बाद, इस प्रक्रिया का दूसरा चरण नौ राज्यों — छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा तीन केंद्र शासित



प्रदेशों — अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में चलाया जा

रहा है।

गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ डीएमके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल, अमित आनंद तिवारी और वकील विवेक सिंह की दलीलों पर सुनवाई कर रही थी कि चुनाव वाले तमिलनाडु में पार्षदिक विसंगतियों की सूची में शामिल मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए पर्याप्त समय और अवसर दिया जाए।

सर्वोच्च न्यायालय तमिलनाडु में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया में मनमानी और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं

■ शेष पेज 2...

सीतारमण द्वारा...

और मजबूती देगा। राजनीतिक और आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार नौ वर्षों तक एक ही वित्त मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाना नीति निर्माण में निरंतरता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। इससे निवेशकों और उद्योग जगत को भी स्थिरता का संदेश मिलता है। साथ ही, यह उपलब्धि महिलाओं की नेतृत्व भूमिका को भी मजबूती से सामने लाती है, जो भारतीय राजनीति और प्रशासन में बढ़ती भागीदारी का संकेत है। कुल मिलाकर, वित्त मंत्री निर्मला सीता.रमण द्वारा लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश किया जाना न केवल एक व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि यह भारत के संसदीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, यह क्षण देश के लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और निरंतर विकास यात्रा का प्रतीक है।

नागरिक सचिव अटल ...

4जी मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करना है जहां अभी तक यह सुविधा नहीं पहुंची है। यह परियोजना भारत सरकार के यूनिवर्सल सर्विस ऑब्सेशन फंड (यूएसओएफ) के तहत कार्यान्वित की जा रही है और बीएसएनएल कार्यकारी एजेंसी है।

सचिव ने आगे बताया कि सभी चिन्हित स्थानों पर भूमि का आवंटन हो चुका है और विद्युत विकास विभाग (पीडीडी) के सहयोग से अधिक. 18 स्थलों पर बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे स्थापना और चालू करने के कार्यों में तेजी लाएं, विशेष रूप से उन 269 स्थलों के लिए जिन्हें 31 मार्च, 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, और शेष स्थानों के लिए अनुमोदन प्रक्रिया में तेजी लाएं।

बैठक में 1,421 सीमावर्ती गांवों को कवर करते हुए सीमावर्ती गांवा. में कनेक्टिविटी की स्थिति की भी समीक्षा की गई और डिजिटल विभाजन को पाटने और सेवा वितरण को बेहतर बनाने के लिए रणनी. तिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निर्बाध कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया।

कॉल बिफोर यू डिग (सीबीयूडी) प्लेटफॉर्म की समीक्षा करते हुए, मुख्य सचिव ने भूमिगत उपयोगिताओं को नुकसान से बचाने के लिए सभी विभागों और एजेंसियों द्वारा इसके उपयोग का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि इस मामले की नियमित रूप से जिला स्तरीय दूरसंचार समिति (डीएलटीसी) की बैठकों के माध्यम से निगरानी की जाए, जो अब सभी जिलों में आयोजित की जा रही हैं।

संशोधित भारत नेट कार्यक्रम (एबीपी) की भी विस्तृत समीक्षा की गई। बताया गया कि डिजिटल भारत निधि द्वारा वित्त पोषित और दूरसंच. र विभाग के स्वामित्व वाली इस परियोजना का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को न्यूनतम 98 प्रतिशत नेटवर्क अपटाइम के साथ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर, जम्मू में नेटवर्क संचालन केंद्र (एनआ. सी) की स्थापना, केंद्रीकृत बिलिंग व्यवस्था और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से अंतर-विभागीय मुद्दों का समाधान जैसी प्रमुख उपलब्धियां हासिल की गई हैं।

5जी की तैयारियों के संबंध में, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) सुविधा, 5जी स्ट्रीट फर्नीचर मैपिंग और क्षमता निर्माण के लिए की गई पहलों पर प्रकाश डाला, जिसमें दूरसंचार विभाग (डीओटी) के सहयोग से नवंबर 2025 में आयोजित 5जी और आरओडब्ल्यू पर एक दिवसीय कार्यशाला भी शामिल है।

मुख्य सचिव ने समृद्ध ग्राम पंचायत पायलट परियोजना के कार्यान्वयन का आकलन किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 2,234 स्कूलों और 1,138 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एफटीटीएच कनेक्टिविटी के माध्यम से डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर डिजिटल कनेक्टिविटी शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और उद्यमिता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण है।

बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने बीएसएनएल, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच घनिष्ठ समन्वय के महत्व पर जोर दिया और परियोजना में देरी से बचने के लिए जिला स्तरीय मुद्दों को शीघ्रता से हल करने का निर्देश दिया। उन्होंने नियमित डीएलटीसी बैठकों और संबंधित तंत्रों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से मुद्दों के समाधान का भी आह्वान किया।

बैठक का समापन मुख्य सचिव द्वारा जम्मू-कश्मीर में सार्वभौमिक डिजिटल कनेक्टिविटी प्राप्त करने के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन प्रमुख परियोजनाओं का समय पर पूरा होना शासन को मजबूत करने, सेवा वितरण में सुधार करने और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश के दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में।

मुख्यमंत्री ने सांबा में...

स्थानीय लोगों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को मौके पर ही सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के हर कोने में

बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि हरमिंदर में रिसीविंग स्टेशन स्थापित करने की यह पहल बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने और क्षेत्र के किसानों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिजली के बुनियादी ढांचे को उन्नत बनाने पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाती है। उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि हरमिंदर तक सड़क संपर्क में सुधार किया जाएगा और सांबा के उपायुक्त को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए मौके पर ही निर्देश दिए।

बाद में, मुख्यमंत्री ने विजयपुर के ठंडी खुई में नवनिर्मित आधुनिक बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया, जिसे सुरक्षित, सुविधाजनक और यात्रियों के अनुकूल परिवहन सुविधाएं प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

इस अवसर पर अधिकारियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस सुविधा को जल्द से जल्द जनता के लिए समर्पित किया जाना चाहिए और इस बस स्टैंड के साथ विकसित अन्य बुनियादी ढांचे का भी उचित उपयोग किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बिजली और परिवहन क्षेत्रों में निवेश महत्वपूर्ण है।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री को सूचित किया गया कि बस स्टैंड में यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं, व्यवस्थित पार्किंग स्थल और आधु. निक डिजाइन की विशेषताएं हैं, जिनका उद्देश्य यातायात जाम को कम करना और जनता के लिए समग्र यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है। उन्हें यह भी बताया गया कि बेहतर कनेक्टिविटी और परिचालन दक्षता सुनिश्चित करके यह सुविधा दैनिक यात्रियों, छात्रों और अन्य यात्रियों को काफी लाभ पहुंचाएगी।

मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी; जिला विकास परिषद के अध्यक्ष केशव दत्त शर्मा, सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया; विजयपुर के विधायक चंद्र प्रकाश गंगा; जेपीडीसीएल के प्रबंध निद. शक गुरपाल सिंह; सांबा की उपविधाकर्ता आयुषी सूडान; जेपीडीसीएल के मुख्य अभियंता, सांबा जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव...

के आरोपों से संबंधित याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था, जिनमें तार्किक विसंगतियों से संबंधित याचिकाएं भी शामिल थीं।

वांगचुक ने सुप्रीम कोर्ट में अरब सिंग की तरह सरकार उखाड़ फेंकने की टिप्पणी करने के आरोपों का खंडन किया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : जोधपुर केंद्रीय जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में उन आरोपों का खंडन किया कि उन्होंने अरब सिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकने का बयान दिया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आलोचना और विरोध करने का उन्हें लो. कतांत्रिक अधिकार है।

वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और पीबी वराले की पीठ के समक्ष कहा कि पुलिस ने हिरासत अधिकारियों को गुमराह करने के लिए चुनिंदा वीडियो का इस्तेमाल किया है।

“वीडियो देखिए। पुलिस के अनुसार, वह कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार राज्य का दर्जा नहीं देगी, तो वह अरब सिंग की तरह सरकार को उखाड़ फेंकेंगे।

उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।” “मैं वीडियो का प्रतिलेख दूंगा,” सिबल ने पीठ को बताया।

अरब सिंग मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में 2010 से 2018 के आसपास फैले सरकार विरोधी प्रदर्शनों, विद्रोहों और सशस्त्र बगावत की एक श्रृंखला है।

सिबल ने इस बात का भी खंडन किया कि वांगचुक ने एक साक्षात्कार में कहा था कि अगर सरकार मदद नहीं करेगी तो लद्दाख के लोग युद्ध के दौरान भारतीय सेना की मदद नहीं करेंगे।

“शूट, यही इस मामले में समस्या है। उन्होंने हिरासत में लेने वाले अधिकारियों को गुमराह किया है। मेरे पास खुद वीडियो का



लिंक है जिसमें वह सरकार और प्रधानमंत्री की प्रशंसा कर रहे हैं; वीडियो में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का विशेष रूप से उल्लेख है। “किसी ने उन्हें (वांगचुक को) बताया कि कारगिल कश्मीर में विलय करना चाहता है। उन्होंने कहा, शटीक है, अगर वे शामिल होना चाहते हैं, तो वे शामिल हो सकते हैं।” जनमत संग्रह से संबंधित कुछ भी नहीं है,” सिबल ने कहा।

सिबल ने वांगचुक के खिलाफ हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ किसी भी अपमान. जनक टिप्पणी के आरोपों का भी खंडन किया और कहा कि किसी आईटी सेल ने इसे गलत तरीके से पेश किया है।

“बिना संपादित संस्करण से पूरी तस्वीर सामने आती है। इसका मतलब यह था कि कश्मीर से लद्दाख को मुक्त कराने के बाद, केंद्र सरकार संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के अपने वादे को पूरा करने में विफल रही।

एसआईआर प्रक्रिया चल रहे राज्यों के लिए सामान्य निर्देश जारी करते हुए, पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है – मैप की गई, मैप नहीं की गई और तार्किक विसंगति।

शीर्ष न्यायालय ने आगे कहा कि श्ताकिक विसंगतिश श्रेणी के अंतर्गत, अधिकारियों द्वारा पिता के नाम या माता-पिता की आयु में विसंगतियां और दादा-दादी की आयु में अंतर देखा गया है। पीठ ने कहा,

ष्षक्षों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में, अन्य बातों के अलावा, पिता के नाम में विसंगति, माता-पिता की आयु में विसंगति, माता-पिता की आयु में 50 वर्ष से अधिक का अंतर, दादा-दादी की आयु में 40 वर्ष से कम का अंतर और छह से अधिक संतानों वाले व्यक्ति शामिल हैं।

जिन व्यक्तियों को अब तक तार्किक विसंगतियों की श्रेणी में रखा गया है, उनकी सहायता के लिए पीठ ने कुछ निर्देश जारी किए। पीठ ने आदेश दिया, “तार्किक विसंगतियों में शामिल व्यक्तियों के नाम प्रत्येक तालुका (उप-मंडल) के ग्राम पंचायत भवनों, सार्वजनिक स्थानों और शहरी क्षेत्रों के वार्ड कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाएं।” पीठ ने आगे

कहा कि प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति अपने अधिकृत प्रति. निधि के माध्यम से अपने दस्तावेज या आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं।

“ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए) भी हो सकता है। ऐसे प्रतिनिधि के पक्ष में एक प्राधिकरण पत्र होना चाहिए, चाहे वह हस्ताक्षरित हो या अंगूठे के निशान से चिह्नित।”

पीठ ने कहा कि पंचायत भवनों या तालुका कार्यालयों में दस्तावेज और आपत्तियां प्रस्तुत करने की अनुमति दी जा सकती है।

इसने चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने को कहा कि पंचायत भवनों में सूचियां प्रदर्शित होने की तिथि से 10 दिनों का अतिरिक्त समय उन सभी व्यक्तियों को दिया जाए जिन्होंने अभी तक अपने दावे, दस्तावेज या आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की हैं, ताकि वे विस्तारित अवधि के भीतर ऐसा कर सकें। पीठ

ने निर्देश दिया, “राज्य सरकार भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग को पंचायत भवनों में दस्तावेजों/आपत्तियों को संभालने और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सुनवाई के लिए पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध कराएगी।” इसने

उनका कहना है कि जिस तरह राम ने सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाकर बाजार में छोड़ दिया था, वैसा ही केंद्र सरकार ने लद्दाख के साथ किया।

उन्होंने राम पर सिर्फ एक प्रतीकात्मक बयान दिया है। अगर इन बयानों के आधार पर किसी को हिरासत में लिया जाता है, तो बेहतर होगा कि हम बोलना ही बंद कर दें। उनकी पत्नी एक धर्मनिष्ठ हिंदू हैं,” सिबल ने कहा। सुनवाई अधूरी रही और 2 फरवरी को जारी रहेगी। अंगमो ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधि. नियम (एनएसए) के तहत वांगचुक की हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने पहले कहा था कि लेह में उनके पति द्वारा दिए गए भाषण का उद्देश्य हिंसा को बढ़ावा देना नहीं बल्कि उसे शांत करना था, और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर उन्हें अपराधी के रूप में पेश किया जा रहा है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि लद्दाख एक निर्मल स्थान है जहां प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है।

“अब कई तरह के निवेश आ रहे हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हुआ। अब अरावली का मामला है। हमें विरोध करना चाहिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर लद्दाख को निर्मल रहना है, तो हम पर्यावरण को नष्ट करने वाली किसी भी तरह की गतिविधि नहीं चाहते,” सिबल ने कहा।

अंगमो ने अदालत को यह भी बताया था कि वांगचुक को उनकी हिरासत के स्पूरे कारण नहीं बताए गए और न ही उन्हें संबंधित प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई के खिलाफ अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया गया।

कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद मौसम में सुधार हुआ, श्रीनगर हवाई अड्डे पर उड़ानें फिर से शुरू हुईं



श्रीनगर

व्यापक हिमपात, तेज हवाओं और बारिश के बाद शनिवार को कश्मीर में मौसम में सुधार हुआ, हालांकि घाटी में रात का तापमान शून्य से नीचे रहा। अधिकारियों ने

बताया कि कुछ क्षेत्रों, विशेषकर कश्मीर के ऊंचे इलाकों में, शुक्रवार देर रात तक रुक-रुक कर हिमपात और बारिश हुई।

शुक्रवार को कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में भारी हिमपात हुआ, श्रीनगर के कुछ हिस्सों में मौसम की पहली हिमपात हुई, हालांकि हल्की रही। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में घाटी के अधिकांश स्थानों, विशेषकर ऊंचे इलाकों में, मध्यम से भारी हिमपात दर्ज किया गया, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की से मध्यम हिमपात हुई।

अधिकारियों ने बताया कि शनिवार सुबह से मौसम में सुधार हुआ है, हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार और रविवार को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और हिमपात का पूर्वानुमान लगाया है। अधिकारियों ने बताया कि

एक और पश्चिमी विक्षोभ सोमवार को जम्मू और कश्मीर को प्रभावित कर सकता है, जिसके प्रभाव से सोमवार रात से मंगलवार सुबह तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/हिमपात होने की संभावना है, और कुछ स्थानों पर गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश भी हो सकती है।

इसके बाद 3 फरवरी तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार रात श्रीनगर में तापमान गिरकर माइनस 1.4 डिग्री

सेल्सियस तक पहुंच गया। श्रीनगर हवाई अड्डे पर भारी बर्फबारी के कारण पहले निर्लंबित की गई उड़ानें रनवे से बर्फ हटाए जाने के बाद फिर से शुरू हो गईं।

उन्होंने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले का गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान माइनस 12.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले का सोनमर्ग पर्यटन स्थल दूसरा सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान माइनस 10.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि दक्षिणी कश्मीर का पहलगाम पर्यटन स्थल, जो वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविरों में से एक है, में तापमान गिरकर माइनस 7.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

कश्मीर घाटी के प्रवेश द्वार माने जाने वाले काजीगुंड में न्यूनतम तापमान -4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कोकरनाग में न्यूनतम तापमान -6.2 डिग्री सेल्सियस और कुपवारा में -4.0 डिग्री सेल्सियस रहा। उन्होंने बताया कि

कश्मीर घाटी इस समय श्विल्ला-ए-कलांश की चपेट में है, जो 40 दिनों की भीषण ठंड की अवधि है। इस दौरान रात का तापमान अक्सर हिमांक बिंदु से कई डिग्री नीचे चला जाता है और बर्फबारी की संभावना सबसे अधिक होती है।

पिछले साल 21 दिसंबर को शुरू हुआ श्विल्ला-ए-कलांश 30 जनवरी को समाप्त होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उच्च न्यायालय प्राथमिक प्रहरी हैं, उन्हें अधिक सक्रिय और कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं के प्रति सतर्क रहना चाहिए

सबका जम्मू कश्मीर

मुंबई : भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने शनिवार को कहा कि उच्च न्यायालयों को कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं के प्रति अधिक सक्रिय और सतर्क रहने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है।

उन्होंने मध्यस्थता और सुलह के तंत्र को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। मुख्य न्यायाधीश यहां दो कार्यक्रमों में बोल रहे थे, एक फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में और दूसरा बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में।

फली नरीमन स्मृति व्याख्यान में अपने भाषण में, मुख्य न्यायाधीश कांत ने उच्च न्यायालयों से कानून के शासन में व्यवस्थागत विफलताओं के प्रति अधिक सक्रिय और सतर्क रहने का आग्रह किया और कहा कि वे अपने दरवाजे पर दस्तक का इंतजार न करें। उन्होंने कहा,

लक्ष्य न्याय तक पहुंच को एक निष्क्रिय अधिकार से राज्य द्वारा गारंटीकृत सेवा में बदलना होना चाहिए। न्याय में देरी न केवल न्याय से इनकार है, बल्कि न्याय का विनाश है।

बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में बोलते हुए, मुख्य न्यायाधीश कांत ने न्यायालय क्षमता से परे विवाद समाधान को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, “न्याय का

भविष्य न केवल विवादों के कुशल निपटारे पर निर्भर करता है, बल्कि उन्हें बुद्धिमत्तापूर्वक सुलझाने पर भी निर्भर करता है। मध्यस्थता, सुलह और मध्यस्थता केवल सुविधा के विकल्प नहीं हैं, बल्कि परिपक्व न्याय के साधन हैं।” उन्होंने आगे कहा कि

ये संबंध बनाए रखते हैं, लागत और देरी को कम करते हैं, और न्यायालयों को उन मामलों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देते हैं जहां वास्तव में आधिकारिक न्यायनिर्णय की आवश्यकता होती है। उन्होंने आग्रह किया,

“न्यायालयों को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां मध्यस्थता को प्रोत्साहित किया जाए। इन तंत्रों की सफलता काफी हद तक एक सक्रिय न्यायालय पर निर्भर करती है जहां न्यायाधीश गंभीरता से वैकल्पिक विवाद समाधान के तरीकों को अपनाने के लिए तैयार हों।” मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि महाराष्ट्र में न्यायपालिका के लिए बजट आवंटन उदार और पर्याप्त है और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक अनुरोध को अत्यंत सम्मानजनक तरीके से और बिना किसी देरी के पूरा किया जाता है।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि उच्च न्यायालयों को केवल पुनरीक्षण या अपील न्यायालय नहीं रहना चाहिए, बल्कि संवैधानिक उपचार के जीवंत और सुलभ केंद्र होने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने जोर दिया कि उच्च न्यायालय केवल सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का माध्यम नहीं हैं। “उच्च न्यायालय आम नागरिक के घर-घर तक पहुंचने वाले प्राथमिक प्रहरी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का शासन कोई दूर की अवधारणा

नहीं बल्कि एक जीवंत, स्थानीय वास्तविकता है,” उन्होंने कहा।

मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि यह वही न्यायालय है जो एक शिशु की पहली चीख सुनता है। “सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय भले ही हो, लेकिन उच्च न्यायालय का निर्णय अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होता है,” उन्होंने अपनी राय व्यक्त की।

मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा, “जब कानून मौन रहता है, तो प्रहरी चुप नहीं रहता। हमने देखा है कि उच्च न्यायालयों ने पर्यावरण संरक्षण, कैदियों सहित प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय संकट के दौरान प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए निर्देश जारी किए हैं।” मुख्य

न्यायाधीश ने उच्च न्यायालयों से डिजिटल युग के अनुरूप मजबूत और अनुकूलित होने का आग्रह किया ताकि न्याय तक पहुंच आसान हो सके। मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि वे अक्सर उन लोगों के खिलाफ मुखर रहते हैं जो उच्च न्यायालय में जाने का उपाय अपनाए बिना सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। उन्होंने कहा, “धनी और विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने की अनुमति है।”

आपातकाल के दौरान फली नरीमन के योगदान को याद करते हुए, मुख्य न्यायाधीश कांत ने कहा कि उथल-पुथल भरे 1970 के दशक ने देश को संवैधानिक चौराहे पर ला खड़ा किया था। उन्होंने कहा कि आपातकाल की घोषणा ने लोकतंत्र की आत्मा की परीक्षा ली थी।

पार्टी लाइन का कभी उल्लंघन नहीं किया, ऑपरेशन सिंदूर पर अपने रुख के लिए माफी नहीं मांगेंगे : शशि थरूर

कोझिकोड (केरल)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि उन्होंने संसद में पार्टी के घोषित रुख का कभी उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि सैद्धांतिक रूप से उनकी एकमात्र सार्वजनिक असहमति ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थी।

केरल साहित्य महोत्सव में एक सत्र के दौरान सवालियों के जवाब देते हुए थरूर ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया था और वे इस पर प्लेड नहीं जताएंगे।

उनका यह बयान हाल ही में आई उन खबरों के बीच आया है जिनमें थरूर के पार्टी नेतृत्व से मतभेद की बात कही गई है।

ऐसी अटकलें हैं कि वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोच्चि में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति को उचित रूप से स्वीकार न करने और राज्य के नेताओं द्वारा उन्हें कथित तौर पर बार-बार दरकिनार करने के प्रयासों से नाराज हैं।

अपनी बात स्पष्ट करते हुए थरूर ने कहा कि एक पर्यवेक्षक और लेखक के रूप में उन्होंने पहलगाम घटना के बाद एक अखबार में लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस घटना को बिना सजा के नहीं छोड़ा जाना चाहिए और इसका कड़ा जवाब दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि भारत विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, इसलिए उसे पाकिस्तान के साथ लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में नहीं घसीटा जाना चाहिए और कोई भी कार्रवाई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाने तक ही सीमित होनी चाहिए।

थरूर ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि भारतीय सरकार ने ठीक वही किया जो उन्होंने सुझाया था।

थरूर ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने ही वह प्रसिद्ध प्रश्न पूछा थारू अंगर भारत मर जाए तो कौन जिएगा? उन्होंने कहा, प्लेज भारत दांव पर हो, जब भारत की सुरक्षा और विश्व में उसका स्थान दांव पर हो, तो भारत सर्वोपरि है। उन्होंने

आगे कहा कि बेहतर भारत के निर्माण की प्रक्रिया में राजनीति दलों के बीच मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय हित दांव पर हों, तो भारत को ही सर्वोपरि होना चाहिए।

रांची में आदिवासी समूहों के साथ बातचीत के दौरान भागवत ने विविधता में एकता के महत्व पर जोर दिया

सबका जम्मू कश्मीर

रांची : आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने शनिवार को यहां आदिवासी समूहों के साथ एक बंद कमरे में हुई बातचीत के दौरान श्विविधता में एकता के महत्व पर जोर दिया। एक प्रतिभागी ने बताया कि

भगवत ने इस दौरान आदिवासी समूहों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को सुना, जिनमें धर्मांतरण, पीईएसए नियमों में कथित खामियां और आदिवासी सूची से नाम हटाने जैसे मुद्दे शामिल थे। कांग्रेस विधायक रामेश्वर ओरांव की बेटी नीशा ओरांव ने पत्रकारों को बताया,

“अपने समापन भाषण में भगवत ने कहा कि भारतीय परंपरा और धर्म हमें विविधता में एकता सिखाते हैं। रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। भारतीय धर्म हमें सिखाता है कि सभी अलग-अलग रास्ते सही हैं और उनमें से कोई भी गलत नहीं है। यही सनातन, हिंदू और भारतीय धर्म है।”

झारखंड में लागू पीईएसए नियमों में कथित खामियों के खिलाफ मुखर रहने वाली ओरांव ने कहा कि उन्होंने बातचीत के दौरान भगवत के सामने यह मुद्दा उठाया था।

“मैंने उन्हें बताया कि नियमों में प्रथागत कानूनों, सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों का कोई उल्लेख नहीं है, जो अधिनियम का मूल आधार हैं। इस खामी से आदिवासी समुदायों को भारी नुकसान होगा। यह आदिवासी लोगों के हित में नहीं है,” उन्होंने कहा।

अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के अधिकारों को मान्यता देने वाला पीईएसए अधिनियम 1996 में लागू किया गया था। राज्य सरकार ने 23 दिसंबर, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी के बाद 2 जनवरी को पीईएसए नियमों को अधिसूचित किया।

सुबह करीब 10.30 बजे शुरू हुई पांच घंटे की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अजुन मुंडा और चंपाई सोरेन, पूर्व भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और अन्य आदिवासी नेता शामिल हुए।

झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर आए भागवत ने शुक्रवार को संघ के राज्य नेतृत्व से मुलाकात की।

माननीय हाई कोर्ट के आदेश को नज़रअंदाज़ करना या किसी बड़ी त्रासदी का इंतज़ार करना?

गाज़ीपुर डेयरी फार्म सोशल मीडिया पर मौत की धमकियों, अवैध कब्जों और आपराधिक नेटवर्क का अड्डा बन रहा है

मनोज भाटी

दिल्ली/पूर्वी ज़ोन : माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के साफ आदेशों के बावजूद, गाज़ीपुर डेयरी फार्म से अवैध कब्जों को हटाने में हो रही देरी अब सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही से कहीं ज़्यादा लग रही है; यह संभावित आपराधिक घटनाओं को न्योता देने जैसा लग रहा है। याचिकाकर्ता मनोज भाटी, जो गाज़ीपुर डेयरी फार्म के स्थानीय निवासी हैं, का पक्का मानना छह है कि गाज़ीपुर डेयरी फार्म इलाके में अवैध झुगियाँ अवैध कब्जे, धमकियों, हिंसा, जाली दस्तावेज़ों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का अड्डा बन गई हैं।

‘सोशल मीडिया पर मौत की धमकियों और अवैध कब्जों का गठजोड़’

हाई कोर्ट का आदेश साफ है कि इन अवैध झुगियों को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए ये कब्जे आपराधिक गतिविधियों की जड़ हैं। इसके बावजूद, अगर कार्रवाई होने से पहले गाज़ीपुर डेयरी फार्म में या उसके आसपास कोई हत्या, दंगा या कोई गंभीर अप्रिय घटना होती है, तो इसकी ज़िम्मेदारी सिधे उन अधिकारियों पर तय की जानी चाहिए जिन्होंने समय पर कार्रवाई नहीं की। सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुलेआम मौत की धमकियाँ देना भारतीय कानून के तहत एक जघन्य अपराध है, और इसे नज़रअंदाज़ करना कानून के शासन पर सीधा हमला है।

स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर /मोनिखान/डबदपॉइंट-रू नाम की प् से धमकियाँ सामने आती हैं। याचिकाकर्ता को सूर्या बुलेटिन चैनल के साथ एक इंटरव्यू के दौरान मौत की धमकी मिली, जो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अवैध झुगियों को हटाने के विरोध में थी।

स्क्रीनशॉट के ज़रिए कैप्चर किए गए वीडियो क्लिप में साफ दिखता है कि मोनिखान एक सार्वजनिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल कर रहा है और इलाके में अपना प्रभाव गलत तरीके से दिखा रहा है, जिससे उसे और बढ़ावा मिल रहा है। ‘गाज़ीपुर डेयरी फार्म में अवैध झुगियों और आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग’

शिकायतकर्ता के अनुसार, यह प् गाज़ीपुर डेयरी फार्म में नूरानी मदरसा मस्जिद और मेट्रो सर्विस सेंटर के पास स्थित झुगियों से चलाई जा रही है। जिस मोबाइल फोन से यह प् चलाई जा रही है, उसकी तत्काल डिजिटल और तकनीकी जांच करने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

Ignoring the Honorable High Court's Order or Waiting for a Major Tragedy?

Ghazipur Dairy Farm: A Hotbed of Death Threats, Illegal अपराधों and Criminal Networks on Social Media!

Report: Petitioner: Manoj Bhati, Delhi / East Zone

Illegal Slums अवैध झुगियाँ **Social Media Threats सोशल मीडिया धमकी** **Forged Aadhaar Gangs जाली आधार गिरोह**

Remove Illegal Encroachments, Crack Down on Criminal Networks!

Is Dr. Sabir Harboring Radical/Jihadist Elements?

Suspicious Documents फर्जी दस्तावेज़ **Fake Documents फर्जी दस्तावेज़**

Duplicate Aadhaar ज़िहादी तार जुड़े? **Jihadist Ties? ज़िहादी तार जुड़े?**

Petitioner Manoj Bhati **Warning to Delhi Police: If Immediate Action Isn't Taken, Ghazipur Could Become a Death Zone!**

Rohingya **Bangladeshi** **Radical Traders** **ववरायी**

याचिका में यह भी कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति डॉ. साबिर के साथ रहता है। अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर होने की आड़ में कट्टरपंथी या ज़िहादी तत्वों को पनाह दे रहा है, तो यह न सिर्फ पेशे की गरिमा पर सवाल उठाता है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है। जघन्य अपराधियों से जुड़े डॉक्टर को सामान्य या माफ़ करने लायक नहीं माना जा सकता। डुप्लीकेट आधार कार्ड गैंग का बार-बार सामने आना यह बताता है कि मोनिखान जैसे

सैकड़ों अवैध अप्रवासी और धोखेबाज़ पुलिस प्रशासन के साथ चूहे-बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। कार्रवाई में देरी उन्हें समय, हिम्मत और खुद को संगठित करने का मौका दे रही है। यह स्थिति दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाती है। भले ही गाज़ीपुर पुलिस स्टेशन केंद्र सरकार के तहत आता हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन न करना न सिर्फ लापरवाही की ओर इशारा करता है, बल्कि संभावित मिलीभगत की

ओर भी।

‘गाज़ीपुर डेयरी फार्म अपराधियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना’

यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी गाज़ीपुर डेयरी फार्म इलाके में घरों में सेंधमारी, हमले और गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। इसके बावजूद, इलाके का क्राइम रिकॉर्ड साफ दिखाने की कोशिश एक जानबूझकर किया गया धोखा लगता है, जिसमें खुफिया एजेंसियां छऔर हेरफेर की गई खुफिया जानकारी शामिल है।

एक बांग्लादेशी परिवार, जो खुद को पश्चिम बंगाल का बता रहा है और हाउसकीपिंग में काम करने के झूठे बहाने से दिल्ली बॉर्डर के पास रह रहा है, इसमें शामिल है। उनका नेटवर्क बांग्लादेश से पूरे भारत में फैला हुआ है, और आरोप है कि वे नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल हत्याओं और दूसरे अपराधों को करने के लिए कर रहे हैं। यह परिवार अभी झुगरी नंबर 123, 119, गाज़ीपुर डेयरी फार्म, दिल्ली में रहता है, और मदरसारू आशिकिया सालमिया अहमदुल उलूम – सीमापुरी, अंसार खान – (इमाम) और पड़ोस की अवैध नूरानी मस्जिद मदरसा से भी जुड़ा हुआ है।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लालच और अवैध उगाही देश की आंतरिक सुरक्षा से समझौता कर रही है। अगर माननीय हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी अपराधी बेखौफ रहते हैं, तो इसे प्रशासनिक व्यवस्था की गंभीर विफलता माना जाएगा।

अब समय आ गया है कि गाज़ीपुर डेयरी फार्म में अवैध कब्जों के खिलाफ बिना किसी दबाव या भेदभाव के तुरंत और निर्णायक कार्रवाई की जाए। नहीं तो, अगर कोई अप्रिय घटना होती है, तो नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारी संबंधित अधिकारियों पर तय की जानी चाहिए। ऐसी संभावित लेकिन बार-बार मिलने वाली जानकारियों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, इंटेलिजेंस ब्यूरो (पु) और संबंधित एजेंसियों को रूढ़िवादी दस्तावेज़ों की जांच करने, शादी के रजिस्ट्रेशन/निकाह के रिकॉर्ड की पुष्टि करने, और इलाके में आवाजाही पर नज़र रखने की ज़रूरत है।

फिलहाल, यह रिपोर्ट स्थानीय खुफिया जानकारी, संदेह और शुरुआती आकलन पर आधारित है। अगर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा समय पर निगरानी और जांच की जाती है, तो गाज़ीपुर मंडी-डेयरी फार्म इलाके में काम करने वाले कश्मिरी व्यापारियों, अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों और रोहिंया मुसलमानों की संदिग्ध गतिविधियों की असली सच्चाई सामने आ सकती है।

याचिकाकर्ता मनोज भाटी

+91 98998 80288

खामोशी से मचेगा शोर : जब एक फिल्म नाम और लेखक के भरोसे सिनेमाघरों में उतरेगी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारतीय सिनेमा में अमूमन फिल्मों का शोर बड़े सितारों और चकाचौंध से शुरू होता है। लेकिन 20 फरवरी को रिलीज़ होने जा रही फिल्म ‘अस्सी’ ने एक नया और साहसी रास्ता चुना है। फिल्म के मेकर्स ने अब तक न तो किसी कलाकार का चेहरा दिखाया है और न ही निर्देशक के नाम का ढोल पीटा है। चर्चा है तो सिर्फ एक शीर्षक कीकृशअस्सी, और इसे बुनने वाले कलमकार कीकृगौरव सोलंकी।

लेखक ही जब फिल्म का श्वेहराश बन जाए हिंदी सिनेमा के इतिहास में यह कम ही देखा गया है कि किसी फिल्म की मार्केटिंग का आधार उसकी स्टारकास्ट नहीं, बल्कि उसका लेखक हो। लेखक गौरव सोलंकी, जिन्होंने अपनी लेखनी से जटिल सामाजिक मुद्दों को हमेशा नया आयाम दिया है, इस बार एक श्वदृश्यर फिल्म को अपनी कहानी के दम पर दर्शकों के बीच ले आए हैं। उनका मानना है

कि सिनेमा का असली हीरो विचार होता है, चेहरा नहीं।

‘अस्सी’ : एक फिल्म, जो सवाल बनकर लौटती है ट्रेलर के आने के बाद से ही फिल्म की कहानी को लेकर कयासों का बाज़ार गर्म है। यह एक तीखा कोर्टरूम ड्रामा है, जो एक स्त्री पर हुए अपराध के बाद की उस कानूनी और सामाजिक कशमकश को दिखाता है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। गौरव सोलंकी कहते हैं, ‘अस्सी वह बिंदु है जहाँ न्याय और अन्याय के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है। यह फिल्म सिनेमाघर में खत्म नहीं होती, बल्कि वहां से तो यह दर्शक के भीतर सवाल बनकर शुरू होती है।

एक इंजीनियर की कलम का जादू

गौरव का अपना सफर भी किसी फिल्म से कम नहीं है। एक छोटे कस्बे से निकलना, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करना और फिर एक सुरक्षित करियर छोड़ मुंबई की अनिश्चित गलियों में अपनी कहानियों के लिए लड़ना।

गौरव का यही अनुभव उनकी कहानियों में वह शकच्चापनश और शस्च्चाईर लाता है, जो आज के दर्शकों, खासकर युवाओं (लमद) को अपनी ओर खींच रहा है।

कंटेंट-ड्रिवन सिनेमा का नया अध्याय

‘अस्सी’ को एक अर्जेंट वॉचर यानी ऐसी फिल्म कहा जा रहा है जिसे आज के समय में देखना अनिवार्य है। यह फिल्म उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो मानते हैं कि बॉलीवुड सिर्फ फॉर्मूला फिल्मों पर चलता है।

बिना किसी ताम-झाम के, केवल एक मज़बूत कहानी और लेखक के भरोसे फिल्म का आना यह साबित करता है कि अब दर्शक कंटेंट का भूखा है।

20 फरवरी को जब ‘अस्सी’ सिनेमाघरों में लगेगी, तो यह सिर्फ एक फिल्म की रिलीज़ नहीं होगी, बल्कि उस सोच की परीक्षा होगी जो कहती है कि कहानी ही सबसे बड़ी स्टार है।

भारतीय गणराज्य पर हिंदुत्व-कॉर्पोरेट गठजोड़ का हमला



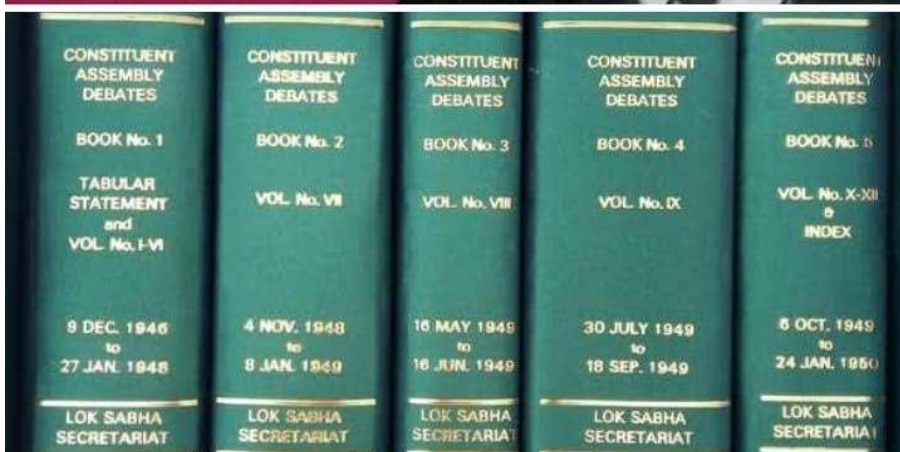
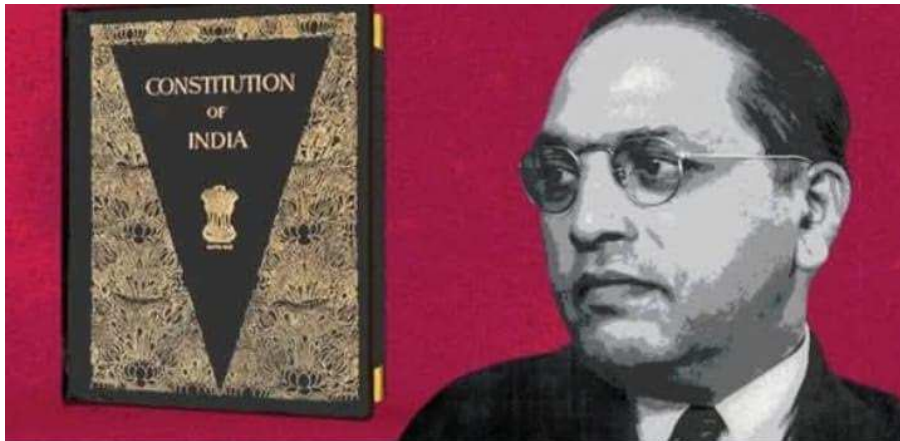
डॉ. सिद्धार्थ रामू

26 जनवरी 1950 को भारत को लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था और भारतीय संविधान को पूरी तरह लागू किया गया था। गणतांत्रिक लोकतंत्र में जन्म के आधार पर किसी को भी स्वाभाविक तौर पर बड़ा नहीं माना जाता है, न तो कोई विशेषाधिकार प्राप्त होता है और न ही किसी भी आधार पर राज्य का कोई पद किसी के लिए जन्म के आधार पर आरक्षित होता है।

भारत में वर्ण-जाति व्यवस्था पूरी तरह से जन्म-आधारित विशेषाधिकार और अधिकार विहीनता पर टिकी हुई थी, जिसमें लिंग के आधार पर महिलाओं पर पुरुषों को भी विशेषाधिकार और वर्चस्व प्राप्त था। जन्म और लिंग-आधारित विशेषाधिकार ही ब्राह्मणवाद का मूलतत्व रहा है। इसको खारिज करते हुए डॉ. आंबेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव डाली। उन्हें लोकतांत्रिक गणतंत्र कितना प्रिय था, इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जिस पार्टी की नींव डाली, उस पार्टी का नाम उन्होंने 'द रिपब्लिकन (गणतांत्रिक) पार्टी ऑफ इंडिया' रखा।

इस 26 जनवरी 2026 को भारतीय गणतंत्र के 76 वर्ष पूरे हो गए। डॉ. आंबेडकर ने यह उम्मीद की थी कि भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की नींव धीरे-धीरे मजबूत होती जाएगी और यह काफी हद तक हुई भी। जिसका परिणाम है कि वैचारिक तौर पर वर्ण-जाति की पक्षधर आरएसएस-भाजपा को भी अपनी जरूरतों एवं मजबूरियों के चलते ही सही, भारत राज्य के राष्ट्रपति (राष्ट्रपति) के रूप में दलित समाज से आए एक व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ा। लेकिन इस प्रतीकात्मक उपलब्धि के बावजूद भी डॉ. आंबेडकर का भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य गंभीर खतरे में है और इस पर गहरे संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर सबसे बड़ा खतरा हिंदू राष्ट्र का खतरा है, जिसके संदर्भ में डॉ. आंबेडकर ने कहा था कि — “अगर हिंदू राज हकीकत बनता है, तब वह इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा। हिंदू कुछ भी कहें, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समता और बंधुता के लिए खतरा है। इन पैमानों पर वह लोकतंत्र के साथ मेल नहीं खाता है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए।” (पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इण्डिया, पृ.338). हिंदू धर्म पर आधारित हिंदू राष्ट्र डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य के भारत के स्वप्न को धूल-धूसरित करता है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की पूरी परिकल्पना जन्मगत श्रेष्ठता एवं निम्नता और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व पर आधारित है, जिसे किसी भी रूप में डॉ. आंबेडकर अपने लोकतांत्रिक गणराज्य में जगह देने के लिए तैयार नहीं थे।

पुरुषों के वर्चस्व से महिलाओं की स्वतंत्रता और स्त्री-पुरुष के बीच समता के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया और मूलतः यही प्रश्न उनके लिए नेहरू के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने का मूल कारण बना। इसके साथ ही, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हिंदुओं के वर्चस्व एवं विशेषाधिकार का दावा करती है। धार्मिक वर्चस्व एवं विशेषाधिकार के लिए भी डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य में कोई जगह नहीं थी। उन्होंने लिखा है कि — “हिंदू धर्म एक ऐसी राजनैतिक विचारधारा है, जो पूर्णतः लोकतंत्र-विराधी है और जिसका चरित्र फासीवाद और/या नाजी विचारधारा जैसा ही है। अगर हिंदू धर्म को खुली छूट मिल जाए — और हिंदुओं के बहुसंख्यक होने



का यही अर्थ है — तो वह उन लोगों को आगे बढ़ने की नहीं देगा, जो हिंदू नहीं हैं या हिंदू धर्म के विरोधी हैं। यह केवल मुसलमानों का दृष्टिकोण नहीं है। यह दमित वर्गों और गैर-ब्राह्मणों का दृष्टिकोण भी है (सोर्स मटियरल आन डॉ. आंबेडकर, खण्ड 1, पृष्ठ 241, महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)।

उपरोक्त उद्धरण में डॉ. आंबेडकर साफ शब्दों में हिंदू राष्ट्र को पूर्णतः लोकतंत्र विरोधी और मुसलमानों तथा अन्य सभी दमित वर्गों के लिए खतरा मान रहे हैं। डॉ. आंबेडकर के लोकतांत्रिक गणराज्य की परिकल्पना और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना दो बिलकुल विपरीत ध्रुव हैं, दोनों के बीच कोई जोड़ने वाला सेतु नहीं है। यदि हिंदू राष्ट्र फलता-फूलता है, तो डॉ. आंबेडकर द्वारा स्थापित भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य खतरे में है। फिलहाल भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य के समुख हिंदू राष्ट्र का गंभीर खतरा आ उपस्थित हुआ है, इस खतरे से भारतीय गणतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है, जो लोकतांत्रिक गणतंत्र की डॉ. आंबेडकर और संविधान सभा के अन्य सदस्यों की परिकल्पना के साथ खड़ा है।

डॉ. आंबेडकर लोकतांत्रिक गणराज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था के साथ सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था के रूप में भी देखते थे। सामाजिक व्यवस्था का उनका मूल आधार समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर टिका हुआ था। उन्होंने अपनी किताब 'जाति के विनाश' में साफ शब्दों में कहा है कि मेरा आदर्श समाज समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित है। समाज के सभी सदस्यों के बीच बंधुता कायम करना उनका लक्ष्य रहा है। बंधुता की इस अवधारणा को उन्होंने गौतम बुद्ध से ग्रहण किया था। आधुनिक युग में फ्रांसीसी क्रांति का भी नारा स्वतंत्रता, समता और भाईचारा ही था। डॉ. आंबेडकर का मानना था कि बंधुता के बिना लोकतांत्रिक गणराज्य सफल नहीं हो सकता है और न ही बंधुता-आधारित राष्ट्र या देश का निर्माण हो सकता है।

भारत में बंधुता के मार्ग में दो बड़ी बाधाएं उन्हें दिखी — सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक असमानता के भारत में दो आधार स्तंभ रहे हैं और हैं — वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों का वर्चस्व। उनका मानना था कि वर्ण-जाति व्यवस्था और महिलाओं पर पुरुषों के वर्चस्व के खाले के बिना सामाजिक समता और स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती है और बिना समता और स्वतंत्रता के बंधुता कायम नहीं हो सकती है। उन्होंने बार-बार रेखांकित किया है कि बंधुता सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों के बीच कायम हो सकती है, जो समान और स्वतंत्र हों। यानी बंधुता की अनिवार्य शर्त समता

और स्वतंत्रता है। डॉ. आंबेडकर की किताब 'जाति का विनाश' बंधुता के लिए सामाजिक समता और स्वतंत्रता की अनिवार्यता को स्थापित करती है और उन सभी चीजों के विनाश का आह्वान करती है, जो सामाजिक असमानता की जनक वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करती हो, जिसमें हिंदू धर्म और वे सभी हिंदू धर्मग्रंथ दोनों शामिल हैं, जो वर्ण-जाति व्यवस्था का समर्थन करते हैं।

यूरोप-अमेरिका के पूंजीवादी समाज के अपने निजी अनुभव और अध्ययन के आधार पर डॉ. आंबेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि आर्थिक असमानता के रहते हुए बंधुता कायम नहीं हो सकती है। भारत में वर्तमान समय में आर्थिक असमानता की खाई चौड़ी से चौड़ी होती जा रही है। आंकड़े इसका साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं।

देश के 1 प्रतिशत लोगों के हाथ में देश की कुल संपदा का 40 प्रतिशत और 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में कुल संपदा का 65 प्रतिशत केंद्रित हो गया है। साफ है कि देश के 90 लोगों के पास सिर्फ देश की कुल संपदा का सिर्फ 35 प्रतिशत है। इसी प्रकार, देश में ऊपर के 10 प्रतिशत लोगों की जेब में देश की कुल आय का 58 प्रतिशत जा रहा है, जबकि नीचे के 50 प्रतिशत लोगों को देश की कुल आय के सिर्फ 15 प्रतिशत पर ज़िंदगी जीनी पड़ रही है। (स्रोत रू वर्ल्ड इन-इक्वैलिटी लैब, द इंडियन एक्सप्रेस, 11 दिसंबर, दिल्ली संस्करण)

इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारतीयों के बीच में संपदा और आय की असमानता की यह खाई साल-दर-साल चौड़ी होती जा रही है। 2022 में भारत के 10 प्रतिशत (14 करोड़) ऊपरी लोगों के हाथ में देश की कुल संपदा का 57 प्रतिशत था, जो पिछले तीन सालों में बढ़कर कुल संपदा का 65 प्रतिशत हो गया है। मतलब 7 प्रतिशत देश की और संपदा उनके हाथ में चली गई। दूसरी तरफ देश के 1 अरब 26 करोड़ लोगों के पास कुल मिला कर देश की कुल संपदा का सिर्फ 35 प्रतिशत जीने-मरने के लिए है।

सवाल यह है कि आखिर ये 14 करोड़ लोग किस सामाजिक समूह और वर्गीय समूह के हैं? इन लोगों में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी में 10.50 करोड़ आदिवासी (एसटी) थे। वर्तमान में कम से कम इनकी आबादी 12 करोड़ है। ऊपर के सबसे धनी 14 करोड़ लोगों में शायद ही कोई आदिवासी हो। तब क्या इन 14 करोड़ लोगों में कोई दलित है? 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में दलितों (एससी) की कुल आबादी देश की कुल आबादी का 16.6 प्रतिशत थी, यानी 20.13 करोड़। इस समय

करीब 24 करोड़ होगी। ऊपर के सबसे धनी 10 प्रतिशत में मुश्किल से कुछ अंगुलियों पर गिनने लायक दलित होंगे, शायद न भी हों।

फिर इन 14 करोड़ लोगों में कितने अति पिछड़े हैं? ये देश की कुल आबादी का करीब 30 से 35 प्रतिशत है — आज की तारीख में 40 करोड़ से अधिक। इनमें से मुश्किल से ही कोई अति पिछड़ा मिले।

इन 14 करोड़ लोगों में कितने अन्य पिछड़े वर्ग हैं? इनकी आबादी देश की कुल आबादी का आधे से अधिक हैं — मतलब आज की तारीख में 70 करोड़ के आसपास। इनमें से कुछ लोग ही या ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के लोग ही इन 14 करोड़ लोगों में शामिल होंगे।

साफ है कि इस संपदा के मालिकों में बहुलांश इस देश में द्विज-सर्वण जातियों (अपरकॉस्ट) या पिछड़े की अगड़ी जातियों के लोग हैं। उसमें भी इन जातियों का एक बड़ा हिस्सा इससे बाहर होगा।

इन 14 करोड़ लोगों में कितने मजदूर हैं? भारत सरकार के 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, कुल कार्यरत लोग 64.33 करोड़ लोग थे। इन सभी कार्यरत कर्मचारियों-मजदूरों में से 31.2 करोड़ असंगठित क्षेत्र में हैं। यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि इसमें से एक भी व्यक्ति इन 14 करोड़ लोगों में शामिल नहीं होगा।

इन 14 करोड़ लोगों में कितने किसान हैं? एक रिपोर्ट के अनुसार, 15.9 करोड़ लोग कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं और 6.84 करोड़ परिवार पूरी तरह कृषि पर निर्भर हैं। एक परिवार का औसत आकार 4.9 मानने पर इनकी कुल संख्या 33.5 करोड़ है। इनमें से किसी के ऊपर के इन 14 करोड़ लोगों में शामिल होने की कोई दूर-दूर तक संभावना नहीं है।

इसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के 1 प्रतिशत लोगों (1.40 करोड़) के हाथ में देश की कुल संपदा का 40 प्रतिशत केंद्रित हो गया है। इनमें कोई आदिवासी होगा, दलित होगा, अति पिछड़ा होगा या अन्य पिछड़ा होगा, यह करीब-करीब नामुमकिन-सा है। पिछड़ी जातियों की अगड़ी ऐतिहासिक तौर पर शासक जातियों (महाराष्ट्र के मराठा या गुजरात के पटेल और जाट आदि) में से हो सकता है कि कुछ लोग हों। ये 1 करोड़ 40 लाख लोग पूरी संभावना है कि द्विज-सर्वण जातियों (अपरकॉस्ट) के लोग हैं। यह कहने की कोई जरूरत नहीं है कि इसमें मेहनतकश किसानों-मजदूरों में से किसी के होने की कोई संभावना नहीं है।

यह सामाजिक-वर्गीय असमानता सिर्फ संपदा के मालिकाने तक सीमित नहीं है। आय के मामले में भी कमोबेश यही स्थिति है। यह सामाजिक-वर्गीय असमानता सार-दर-साल चौड़ी होती जा रही है। साफ है कि यह दो तरह से हो रहा है — पहला देश में जो संपदा साल-दर-साल सृजित हो रही है, उसका बड़ा हिस्सा ऊपर के 10 प्रतिशत लोग। के हाथ में जा रहा है। दूसरा नीचे के लोगों की संपदा का भी ऊपर के लोगों के हाथों हस्तान्तरण हो रहा है।

लेकिन क्या यह सिर्फ गरीबी-अमीरी या संपदा-आय के अंतर का मामला है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह गरीबी-अमीरी और उससे जुड़े सुख-दुख और शोषण-उत्पीड़न का मामला तो है, लेकिन इससे कम बड़ा मामला यह नहीं है कि जब देश की करीब दो-तिहाई संपदा और आय 10 प्रतिशत लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, तो वह इस देश की आर्थिक नीतियों, प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं को निर्णायक तरीके से प्रभावित करेंगे। इन सब चीजों को अपने हितों-लाभों के अनुसार चलाएंगे। चुनाव में अपनी इस अकूत संपदा और आय का इस्तेमाल ऐसी पार्टी या पार्टियों के लिए करेंगे, जो उनकी इस संपदा और आय को बढ़ाने में मदद करें या बनाए रखने में मदद करें। वे मीडिया का मालिक बनकर और विज्ञापनदाता बनकर तय करेंगे कि कौन-सी सूचना और सामग्री लोगों के पास जाए और कौन-सी न जाए। किस चीज को मुद्रा बनाया जाए और किस चीज को नहीं।

■ शेष पेज 6...

कठुआ विधायक डॉ. भारत भूषण ने वार्ड 6 और 7 में तीन विकास कार्यों का किया उद्घाटन



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, कठुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. भारत भूषण ने बुधवार को नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 और 7 में तीन विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इन कार्यों में गलियों और नालियों का निर्माण

शामिल है, जिन पर कुल 18.50 लाख रुपये की लागत आई है।

इनमें से वार्ड नंबर 7 में दो गलियां और नालियां, जबकि वार्ड नंबर 6 में एक गली और नाली का निर्माण किया गया है। इन कार्यों से क्षेत्र के लोगों को बेहतर सफाई व्यवस्था और आवागमन में सुविधा मिलेगी।

इस मौके पर विधायक डॉ. भारत भूषण ने कहा कि कठुआ में 10 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्य विभिन्न चरणों में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य हर वार्ड तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना और क्षेत्र का समग्र विकास करना है। कार्यक्रम में पूर्व पार्षद अनिरुद्ध शर्मा,

हरबंस लाल, डॉ. शिव कुमार, स्मृति विद्या देवी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष देविंदर सिंह सनी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विधायक ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और जल्द समाधान का आश्वासन दिया। कार्यक्रम के बाद विधायक डॉ. भारत भूषण

ने शहीद कैप्टन सुनील चौधरी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कैप्टन सुनील चौधरी वर्ष 2008 में उत्तर-पूर्व भारत में उग्रवाद के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे और उन्हें सेना मेडल व कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था।

महाराष्ट्र में 2696 करोड़ रु. से तूर (अरहर) की 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दी स्वीकृति

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में बैठक कर महाराष्ट्र में तूर (अरहर) की 3.37 लाख मीट्रिक टन खरीद, जिसकी एमएसपी राशि लगभग 2696 करोड़ रुपए है, को मूल्य समर्थन योजना (पी.एस.एस.) के तहत स्वीकृति दे दी है।

बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने राज्य के विपणन (मार्केटिंग) मंत्री श्री जयकुमार

रावल के साथ खरीद से संबंधित व्यवस्थाओं पर चर्चा की। उन्होंने नेफेड, एन.सी.सी.एफ. और राज्य के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान श्री चौहान ने कहा कि तूर की खरीद के इस निर्णय से केंद्र सरकार को बड़ा वित्तीय भार वहन करना पड़ेगा, परंतु इसके बावजूद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह बहुत जरूरी है कि खरीद सही तरीके से हो। किसानों से

सीधी खरीद से ही बिचौलियों की सक्रियता कम होगी और लाभ वास्तविक किसान तक पहुंच पाएगा। नेफेड और एन.सी.सी.एफ. को समन्वित प्रक्रिया चलाने के केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह ने कहा कि नेफेड और एन.सी.सी.एफ. राज्य सरकार के समन्वय से खरीद प्रक्रिया संचालित करें, ताकि खरीद का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुंच सके।

आधुनिक तकनीक से पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकतम और कारगर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए किसानों के

पंजीकरण की उचित व्यवस्थाएं की जाएं।

किसानों की सुविधा के लिए खरीद केंद्र बढ़ाने पर बल

केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यकता होने पर खरीद केंद्रों की संख्या में इजाफा किया जाए, ताकि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और खरीद व्यवस्था पारदर्शी और प्रभावी रहे।

इस उच्चस्तरीय बैठक में महाराष्ट्र के विपणन मंत्री श्री जयकुमार रावल, केंद्रीय कृषि सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

■ शेष पेज 5 से...

कौन सा मुद्दा उछाला जाए और किसे कब में दफन कर दिया जाए। वे सोशल मीडिया को भी निर्णायक तरीके से प्रभावित करने की स्थिति में हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के मालिकों और उससे आय प्राप्त करने वालों का सारा कारोबार इसी धन से जुड़ा हुआ है। वे नेताओं और नौकरशाहों को अपने अनुकूल और अपने फायदे के लिए काम करने के लिए, नीति बनाने के लिए और नीतियों को लागू करने के लिए निर्णायक तरीके से प्रभावित और संचालित करने की स्थिति में होंगे।

वे अपने इस अकूत संपदा और आय से देश के लोकतंत्र को हाईजैक करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। ये सारे काम वे कानूनी और गैर-कानूनी सभी तरीकों का इस्तेमाल करके करते हैं और करेंगे। इसको भाजपा को मिलने वाले चंदे से समझा जा सकता है। 2023-24 में भाजपा को 2,243 करोड़ चंदा मिला, जबकि इसके पहले के वर्ष में सिर्फ 719 करोड़ चंदा मिला था। एक साल में भाजपा को मिलने वाले चंदे में 211 प्रतिशत की वृद्धि। देश में सभी पार्टियों को मिले कुल चंदे का 88 प्रतिशत चंदा अकेले भाजपा को मिला। जब भाजपा को 2022-23 में 2,243 करोड़ चंदा मिला, तो उसी वर्ष कांग्रेस को सिर्फ 281 करोड़ का सिर्फ चंदा मिला। कहां 2,243 करोड़ और कहां सिर्फ 281 करोड़!

जैसे-जैसे देश के धनिकों की संपदा और आय में वृद्धि हो रही है, उसी दर से भाजपा के चंदे में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। 2004 में भाजपा को सिर्फ 88 करोड़ चंदा मिला था। 2014 में यह 295 करोड़ हो गया। 2019 में यह छलांग लगाकर 3,562 करोड़ रुपया हो गया और 2024 में और तेजी से छलांग लगाकर 10,107 करोड़ हो गया।

देश के मुड़ी भर धनिकों की तेजी से बढ़ती आय और संपदा और भाजपा की तेजी से बढ़ती आय (कानून सम्मत चंदा) के बीच का आनुपातिक रिश्ता

क्या अकारण है? क्या यह सहज-स्वाभाविक परिघटना है? अकारण ही नहीं, संविधान सभा में संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत करते हुए डॉ. आंबेडकर ने यह चेतावनी दी थी कि हम संविधान के माध्यम से जिस राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित कर रहे हैं, उसे सामाजिक और आर्थिक असमानता निगल जाएगी, यदि हम इसे खत्म करने में सफल नहीं हुए। सामाजिक असमानता खत्म तो नहीं हुई, लेकिन आर्थिक असमानता बढ़ती गई और अब तो छलांग लगाकर बढ़ रही है। यह आर्थिक असमानता वहां पहुंच गई है, जहां से वह देश, समाज और लो. कतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है।

सामाजिक समता के साथ आर्थिक समता भी बंधुता की अनिवार्य शर्त है। आर्थिक समता के लिए उन्होंने 'राजकीय समाजवाद' की स्थापना का प्रस्ताव अपनी किताब 'राज्य और अल्पसंख्यक' में रखा। उन्होंने कृषि भूमि के निजी मालिकाने को पूरी तरह खत्म करने और उसका पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव इस किताब में किया है। इसके साथ उन्होंने सभी बड़े और बुनियादी उद्योग-धंधों को भी राज्य के मालिकाने में रखने का प्रस्ताव किया है। कृषि भूमि के पूर्ण राष्ट्रीयकरण और बुनियादी एवं बड़े उद्योग धंधों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण के माध्यम से ही आर्थिक समता हासिल की जा सकती है, यह डॉ. आंबेडकर के चिंतन का एक बुनियादी तत्व है। सामाजिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ब्राह्मणवाद है और आर्थिक समता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा पूंजीवाद है। इन्हीं दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए डॉ. आंबेडकर ने ब्राह्मणवाद एवं पूंजीवाद को कामगारों के सबसे बड़े दो दुश्मन घोषित किया था। आज भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य गंभीर खतरे में है। एक तरफ हिंदू राष्ट्र की परियोजना के नाम पर नए सिरे से नए रूप में वर्ण-जाति व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश चल रही है। दूसरी तरफ सार्वजनिक संपदा और

सार्वजनिक संपत्ति को विभिन्न रूपों में कार्पोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है और इस तरह से डॉ. आंबेडकर के सामाजिक समता और राजकीय समा. जवाद के स्वप्न का खात्मा किया जा रहा है।

डॉ. आंबेडकर की बंधुता की जड़ें बुद्ध धम्म में थीं। उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है कि "सकारात्मक तरीके से मेरे सामाजिक दर्शन को तीन शब्दों में समेटा जा सकता है — मुक्ति, समानता और भाईचारा। मगर, कोई यह न कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से लिया है। बिलकुल नहीं। मेरे दर्शन की जड़ें राजनीतिशास्त्र में नहीं, बल्कि धम्म में हैं। मैंने उन्हें... बुद्ध के उपदेशों से लिया है...। (क्रिस्तोफ़ जाफ़्रलो, पृ. 159) वे बंधुता-आधारित लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए बुद्धमय भारत की कल्पना करते थे। बुद्धमय भारत उनके लिए वर्ण-जाति व्यवस्था पर आधारित वैदिक, सनातन, ब्राह्मणवादी और हिंदू भारत का विकल्प था। बुद्धमय भारत उनके समता, स्वतंत्रता और बंधुता आधारित भारत के स्वप्न का एक अन्य आधार स्तंभ था। डॉ. आंबेडकर के प्रयासों के चलते भारतीय गणराज्य के बहुत सारे प्रतीकों में बौद्ध प्रतीकों को शामिल किया गया। जैसे — राष्ट्रीय ध्वज में धर्मचक्र, प्राचीन भारत के बौद्ध सम्राट अशोक के सिंहों को राष्ट्रीय चिह्न के रूप में मान्यता देना और राष्ट्रपति भवन की त्रिकोणिका पर एक बौद्ध सूक्ति को उत्कीर्ण करना। संविधान में भी उन्होंने बौद्ध धम्म के कुछ बुनियादी तत्वों को समाहित किया। इस संदर्भ में उन्होंने स्वयं लिखा है — "मैं भी हिंदुस्तान में सर्वांगीण पूर्ण तैयारी होने पर बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला हूं। संविधान बनाते समय उस दृष्टि से अनुकूल होने वाले कुछ अनुच्छेदों को मैंने उसमें अंतर्भूत किया है।" (धनंजय कीर, पृ.457) उन्होंने बौद्ध धम्म को वैज्ञानिक चेतना, लोकतांत्रिक मूल्यों और स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना पर खरा पाया, जिसमें ईश्वर और किसी पारलौकिक दुनिया

के लिए कोई जगह नहीं थी। न तो उसमें किसी अंतिम सत्य का दावा किया गया था और न ही कोई ऐसी किताब थी, जो ईश्वरीय वाणी होने का दावा करती हो। गणतंत्रात्मक भारत, बंधुता-आधारित भारत और बुद्धमय भारत — डॉ. आंबेडकर के सपनों के भारत के तीन बुनियादी तत्व थे, लेकिन इन तीनों तत्वों को तभी हासिल किया जा सकता है, जब भारतीय जन प्रबुद्ध बनें। प्रबुद्ध भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने 4 फरवरी 1956 को श्रबुद्ध भारतर नामक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। प्रबुद्ध व्यक्ति एवं समाज वही हो सकता है, जो वैज्ञानिक चेतना से लैस हो और हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसता हो तथा आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हो। डॉ. आंबेडकर स्वयं बीसवीं शताब्दी के सबसे प्रबुद्ध व्यक्तित्वों में से एक हैं। वे हर चीज को एक समाज वैज्ञानिक की दृष्टि से आलोचनात्मक नजरिए से देखते थे और तर्क की कसौटी पर कसते थे। जो कुछ भी उनकी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता था, उसे वे खारिज कर कर देते थे। उन्होंने बौद्ध धम्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा और आलोचनात्मक नजरिए से देखा और उसे नया नाम श्रवयान्श दिया। आरएसएस और कार्पोरेट (ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और ब्राह्मणवादी हिंदू फासीवाद) के गठजोड़ से बन रहा वर्तमान भारत डॉ. आंबेडकर के गणतंत्रात्मक, बंधुता-आधारित, बुद्धमय और प्रबुद्ध भारत की परिकल्पना से पूरी तरह उलट है। हमें डॉ. आंबेडकर की संकल्पना के भारत के निर्माण के लिए इस गठजोड़ का पुरजोर विरोध करना चाहिए और स्वतंत्रता, समता और बंधुता आधारित गणतंत्रात्मक भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ लग जाना चाहिए।

(डॉ. सिद्धार्थ रामू वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और अनुवादक हैं, जो दलित और बहुजन विमर्श तथा आंबेडकर वैचारिकी पर लिखते हैं।)



साप्ताहिक

सबका जन्मू कश्मीर
शंपादकीय

निपाह की चेतावनी



संपादक - राज कुमार

एक बार फिर, एक वायरस ड्रामा के साथ नहीं, बल्कि शांत बेचौनी के साथ आया है, कुछ इन्फेक्शन, एक हॉस्पिटल वार्ड निगरानी में, चिंता, जनक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, और विदेशी एयरपोर्ट्स अपने गेट्स को टाइट कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में रिपोर्ट किए गए निपाह के मामले संख्या में सीमित हो सकते हैं, लेकिन उनके असर आंकड़ों से कहीं ज्यादा बड़े हैं। निपाह भारत के लिए कोई नया खतरा नहीं है। यह पहले भी इस राज्य में और बार-बार केरल में सामने आया है, जिससे इसकी गंभीरता की ऐसी छवि बनी है जो इसके पैमाने से कहीं ज्यादा है। मृत्यु दर जो खतरनाक स्तर तक पहुँच सकती है और कोई स्वीकृत इलाज या वैक्सीन नहीं होने के कारण, यह वायरस पब्लिक हेल्थ में एक अनोखी जगह रखता है, दुर्लभ, लेकिन माफ न करने वाला। इसीलिए एक छोटा सा आउटब्रेक भी अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचता है। एशिया के कुछ हिस्सों में प्रतिक्रिया तेज़ रही है। थाईलैंड और काठमांडू के एयरपोर्ट्स पर, और भारत-नेपाल सीमा पर हेल्थ स्क्रीनिंग अलार्म बजाने का संकेत नहीं है; वे कमजोरी को स्वीकार करना है। एक ऐसे क्षेत्र में जो लोगों, व्यापार और श्रम की लगातार आवाजाही से जुड़ा हुआ है, बीमारी अब भूगोल का सम्मान नहीं करती है। जो एक जिले में शुरू होता है, वह गलत परिस्थितियों में, उससे कहीं दूर के सिस्टम को टेस्ट कर सकता है। पश्चिम बंगाल के लिए, यह पल बहुत महत्वपूर्ण है। हेल्थकेयर सेटिंग से सामने आ रहे इन्फेक्शन एक असहज सच्चाई को उजागर करते हैं हॉस्पिटल अक्सर आउटब्रेक के दौरान पहली और सबसे खतरनाक फ्रंट लाइन होते हैं। जब सुरक्षा प्रोटोकॉल लड़खड़ाते हैं, तो जान बचाने का काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा जोखिम में आ जाते हैं। यह व्यक्तिगत देखभाल की विफलता नहीं है, बल्कि तैयारी की कमी है, एक ऐसा गैप जो हर बार जब कोई दुर्लभ पैथोजन सामने आता है, तो फिर से उभर आता है। बड़ी चुनौती इमरजेंसी रोकथाम से परे है। निपाह एक जूनोटिक बीमारी है, जिसकी जड़ें मानवीय गतिविधि और प्राकृतिक इकोसिस्टम के बीच असहज ओवरलैप में हैं। बढ़ते शहरी किनारे, बाधित वन्यजीव आवास, और अनौपचारिक खाद्य श्रृंखलाएँ स्पिलओवर के लिए बार-बार अवसर पैदा करती हैं। ये स्थितियाँ एपिसेडिक नहीं हैं; ये संरचनात्मक हैं। फिर भी पब्लिक हेल्थ प्रतिक्रियाएँ अक्सर अस्थायी रहती हैं, जो केवल इन्फेक्शन सामने आने पर ही सक्रिय होती हैं। इसमें एक सबक यह भी है कि डर तथ्यों से ज्यादा तेज़ी से फैलता है। हालांकि भारत के बाहर कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पिछली महामारियों की यादें समाजों में गहराई तक बनी हुई हैं। अगर पब्लिक चिंता को मैनेज नहीं किया गया, तो यह कलंक, गलत सूचना और आर्थिक व्यवधान में बदल सकती है। पारदर्शी संचार दृश्य पर, तथ्यात्मक और शांत, खुद मेडिकल हस्तक्षेप जितना ही ज़रूरी हो जाता है। भारत के लिए, और खासकर उन राज्यों के लिए जहाँ उभरती बीमारियों का बार-बार खतरा रहता है, इस घटना से आश्वासन के बजाय चिंतन होना चाहिए। निगरानी प्रणालियों को केवल पता चलने के बाद ही मज़बूत नहीं किया जा सकता। ट्रेनिंग, लेबोरेटरी क्षमता, वन्यजीवों की निगरानी और अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल लगातार काम करना चाहिए, न कि सिर्फ रिएक्शन के तौर पर। जब तैयारी काम करती है तो वह दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वह नहीं होती तो विनाशकारी होती है। इसलिए निपाह का डर सिर्फ एक मेडिकल घटना नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि एक-दूसरे से जुड़ी दुनिया में सामान्य स्थिति कितनी नाजुक बनी रहती है। सवाल यह नहीं है कि ऐसे आउटब्रेक दोबारा होंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हर बार सिस्टम पिछली बार से बेहतर तैयार होगा। अगर मौजूदा मामलों को जल्दी से कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इसे खत्म नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक चेतावनी समझना चाहिए। क्योंकि निपाह का असली खतरा उसका दुर्लभ होना नहीं है, बल्कि जब वह वापस आता है तो वह जिस लापरवाही को उजागर करता है, वह है

शांति प्राप्त करने की कुंजी सहिष्णुता है

वसुधैव कुटुंबकम् (एक गृह, एक परिवार, एक भविष्य) के अपने स्पष्ट आह्वान के साथ भारत को जी20 की साल भर की अध्यक्षता के दौरान शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित किया गया था।

एके मर्चेट

1896 में इंग्लैंड में स्वामी विवेकानन्द ने घोषणा की कि दुनिया को एक नई सभ्यता देने के लिए ईश्वर ने भारत को चुना है और भारत सदियों से ऐसा कर रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत अपनी आध्यात्मिकता से दुनिया को जीत लेगा। हम भारतीयों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है - हमें यह करना होगा या मरना होगा। वसुधैव कुटुंबकम् (एक गृह, एक परिवार, एक भविष्य) के अपने स्पष्ट आह्वान के साथ भारत को 2020 की साल भर की अध्यक्षता के दौरान शक्तिशाली रूप से प्रदर्शित किया गया था। देश की अधिकांश आबादी के लिए आत्मविश्वास का स्तर ऊँचा है।

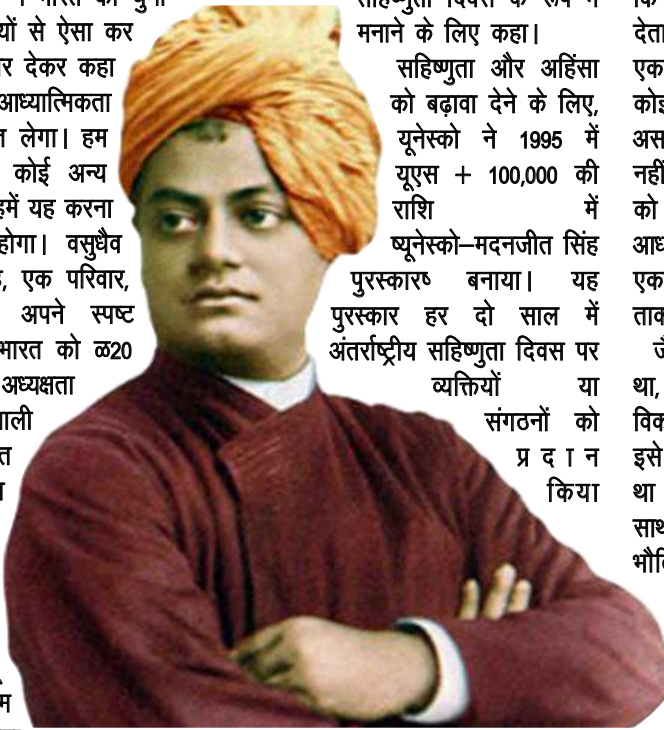
“एकता का तम्बू खड़ा हो गया है; तुम एक दूसरे को पराया न समझो। तुम एक पेड़ के फल हो, और एक शाखा की पत्तियाँ हो” बहाई धर्म के संस्थापक, विवेकानंद के समकालीन, बहाउल्लाह ने 150 साल पहले घोषित किया था। यह मेरा गहरा विश्वास है और गृह पर अधिकांश जीवन के अस्तित्व को खतरे में डालने वाले गंभीर खतरे के बावजूद हम सही रास्ते पर हैं।

समाजों और राष्ट्रों के बीच बढ़ती हिंसा और अजेय ध्रुवीकरण के इन दिनों में संस्कृतियों और लोगों के बीच सहिष्णुता का निर्माण खतरनाक अनुपात में बढ़ गया है। सहिष्णुता दूसरों के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सम्मान है। जब 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई तो उसने तीन वादे किए (प) वह राष्ट्रों को युद्ध में जाने से रोकने की कोशिश करेगा, लड़ाई को रोकेंगे; (पप) सभी मनुष्यों के साथ निष्पक्ष और न्यायपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, चाहे वे कमजोर हों या मजबूत; (पपप) वे राष्ट्र एक-दूसरे को बेहतर और खुशहाल जीवन जीने में मदद करने के लिए मिलकर काम करेंगे।

दुख की बात है कि मानवता तीन वादों में से एक को भी पूरा करने में विफल रही है। साल-दर-साल, राष्ट्र-राज्य बातचीत करने, नीतियाँ तैयार करने, कानूनी दस्तावेज़ तैयार करने, प्रोटोकॉल की समीक्षा करने, संघर्षों को हल करने, मानवीय संकटों को संबोधित करने, विकासवात्मक एजेंडा तैयार करने, जलवायु, आर्थिक और के संबंध में गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करते हैं। राजनीतिक संकट और आपके पास क्या है। जब हम सीखेंगे और बढ़ें होंगे! 1993 में यूनेस्को की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 1995 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया। यूनेस्को की 1995 में सहिष्णुता पर सिद्धांतों की घोषणा थीर सहिष्णुता हमारे विश्व की संस्कृतियों की समृद्ध विविधता, अभिव्यक्ति के हमारे रूपों और मानव होने के तरीकों का सम्मान, स्वीकृति और सराहना है। इस घोषणा ने सहिष्णुता

दिवस की घोषणा के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा की शुरुआत की। एक साल बाद, 1996 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी सदस्य राज्यों से 16 नवंबर को अंतराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाने के लिए कहा।

सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, यूनेस्को ने 1995 में यूएस + 100,000 की राशि में यूनेस्को-मदनजीत सिंह पुरस्कार बनाया। यह पुरस्कार हर दो साल में अंतराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर व्यक्तियों या संगठनों को प्रदान किया



जाता है। वर्ष 2022 के लिए कैमरून के प्रैंका मा-इह सुलेम योंग, गैर सरकारी संगठन रुअफ्रोगिवनेस और पॉजिटिव यूथ्स अफ्रीका के अध्यक्ष ने पुरस्कार प्राप्त किया। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने समाज में मानसिक बीमारी को देखने और प्रस्तुत करने के तरीके पर लोगों की धारणा को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की। कला चिकित्सा और मनोविज्ञान में प्रशिक्षित, वह दो गैर सरकारी संगठनों की संस्थापक और अध्यक्ष बनीं रुअफ्रोगिवनेस मूवमेंट (रुअफ्रो. गिवनेस) और पॉजिटिव यूथ्स अफ्रीका (पीवाईए)। दोनों एनजीओ शांति शिक्षा पहल हैं। उनकी महत्वाकांक्षा नौ अफ्रीकी देशों (कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो, माली, नाइजर, नाइजीरिया, सूडान और टोगो) में अंतरसांस्कृतिक संघर्षों से पीड़ित बच्चे लोगों को कला की सार्वभौमिक भाषा के माध्यम से उनके आघात से उबरने में सक्षम बनाना है। इसके बाद के महीनों में यूरोप और मध्य-पूर्व में युद्धों के कारण दुनिया और भी अधिक आघातपूर्ण और हिंसक हो गई है। यह हमारे देश के लिए चुनौती है, जहां इतने सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, जहां महिलाओं और लड़कियों पर नियमित रूप से हमला किया जाता है, जहां धार्मिक असहिष्णुता व्याप्त है, जहां जाति विभाजन हावी है क्योंकि अस्थायी और सक्षम कोटा प्रणाली वोट बैंक की राजनीति में संस्थागत हो गई है; जहां वर्ग असमानताएँ लगातार राष्ट्रीय स्थिरता को खतरे में डालती हैं, जहां 1,000 से अधिक राजनीतिक दल किसी भी कीमत पर सत्ता हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, आदि। तक। मेरे लिए ये सहिष्णुता के गुण का अभ्यास करने और राष्ट्र-निर्माण में सबसे बड़ी बाधाएँ हैं। विचारणीय बात यह है कि करोड़ों की आबादी वाले देश पर थोड़े से यूरोपीय व्यापारी कैसे शासन कर सकते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि रियासतों के शासक और उनकी प्रजा एकजुट नहीं थे और

उनके लिए अपनी सैन्य श्रेष्ठता के आधार पर औपनिवेशिक आकाओं की झूठी कहानियों का शिकार बनना आसान हो गया था। हम सभी को यह सोचना होगा कि वास्तव में क्या सहिष्णुता को बढ़ावा देता है और हमें असंख्य विविधता के बीच एकजुट होकर रहने में मदद करता है। कोई राजनीतिक प्रक्रिया या कानून असहिष्णुता या गहरे बैठे पूर्वाग्रह को दूर नहीं कर सकता। जो चीज़ वास्तव में भारत को सामंजस्यपूर्ण बनाती है, वह उसकी आध्यात्मिक और नैतिक संस्कृति है - यही एकमात्र चीज़ है जो हमें विभाजनकारी ताकतों के सामने एक साथ रख सकती है। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने समझाया था, आध्यात्मिकता महज बड़े ऐतिहासिक विकासों का प्रतीक मात्र नहीं थी। बल्कि, इसे परिवर्तन के लिए एक साधन बनना था जो व्यावहारिक पश्चिमी बहुलवाद के साथ पूर्वी ज्ञान के मिश्रण से आएगा जो भौतिकवाद के साथ आध्यात्मिकता, असहिष्णुता के साथ सहिष्णुता, वाद्यवाद के साथ पारगमन की तुलना करता था। स्वामीजी ने अपने साथी पुरुषों और महिलाओं को चेतावनी दी थीरू ज्ञाति का विचार सबसे बड़ा विभाजन कारक है... जन्म या योग्यता के सिद्धांत पर सभी जातियाँ बंधन हैं। बहाई लेखन इस बात पर जोर देता है कि हमें इन पूर्वाग्रहों और सामाजिक बाधाओं को पीछे छोड़ना चाहिए और एकजुट समाज की दिशा में काम करना चाहिए। जाति, पंथ और धर्म से विभाजित देश में प्रगति हासिल करना कठिन है। कोई भी देश तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक नागरिक प्रगति कर सके। कानून या सरकार समाज की प्रगति सुनिश्चित नहीं कर सकती। समाज को हमेशा अपनी भलाई के लिए काम करना पड़ता है। जब तक महिलाएं उन्नति नहीं करेंगी तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। संसद में एक तिहाई महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने वाला हालिया विधेयक एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। समाज की विभिन्न सेटिंग्स में सहिष्णुता प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरणों को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता हैरू (1) परिवर्तन के लिए सहयोगात्मक अध्ययन - व्यक्ति का परिवर्तन एक अलग प्रक्रिया नहीं है, न तो तपस्वी है और न ही पूरी तरह से किसी की आत्म-पूर्ति पर केंद्रित है। सभी लोग। के लिए खुले अध्ययन मंडल असहिष्णुता की स्थितियों को खत्म करने और सकारात्मकता बढ़ाने के लिए उपयोगी स्थान हैं। (2) बच्चों की आध्यात्मिक शिक्षा - बच्चे संभावित रूप से दुनिया की रोशनी हैं और साथ ही साथ इसका अंधकार भी हैं।

बच्चों को नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र प्राप्त करने में सहायता के लिए विशेष कक्षाओं की आवश्यकता है। (3) युवाओं को सशक्त बनाना - युवा कार्यक्रमों का उद्देश्य उन्हें उद्देश्य की भावना प्रदान करना, उनका आत्मविश्वास बढ़ाना, सुनने और समस्या सुलझाने की उनकी क्षमता बढ़ाना और जिम्मेदार विकल्प बनाना है। (4) भक्ति सभा - प्रार्थना में ईश्वर की ओर मुड़ने से जीवन की परीक्षाओं और परीक्षाओं से आंतरिक शक्ति और सात्वता मिलती है।

श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर बर्फबारी के बाद यातायात बहाल करने के प्रयास जारी हैं



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : अधिकारियों ने बताया कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर यातायात बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चल रहा है। बर्फबारी के बाद अलग-अलग हिस्सों में फिसलन भरी स्थितियों के कारण ये सड़कें शनिवार को लगातार दूसरे दिन भी बंद रहीं। अधिकारियों ने बताया कि

270 किलोमीटर लंबे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों यात्रियों को सेना, पुलिस और नागरिक प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और उन्हें भोजन और आश्रय प्रदान किया गया। यह राजमार्ग कश्मीर को देश के शेष भाग से जोड़ने वाला एकमात्र बारहमासी मार्ग है।

पुलिस उपाधीक्षक, राष्ट्रीय राजमार्ग (बनिहाल), एसपी सिंह ने बताया कि एनएच44 पर बर्फ हटाने का अभियान अंतिम चरण में है और दोनों ओर फंसे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर निकाला जाएगा।

राजमार्ग के रामबन खंड में 900 से अधिक वाहन फंसे हुए हैं, जबकि आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रकों सहित 2,000 से अधिक अन्य वाहन जम्मू, उधमपुर, कुलगाम और अनंतनाग जिलों में अपने गंतव्यों की ओर जाने के लिए हरी झंडी का इंतजार कर रहे हैं।

डीएसपी ने बताया, "रामसू-बनिहाल सेक्टर के कुछ हिस्सों में राजमार्ग फिसलन भरा है और सड़क सफाई एजेंसियां घ्यसुरक्षित ड्राइविंग के लिए स्थिति सुधारने के लिए सड़क पर नमक और यूरिया का छिड़काव कर रही हैं।" उन्होंने आगे कहा कि फंसे हुए

वाहनों को हटाने के बाद सामान्य यातायात बहाल होने की संभावना है।

एनएच-44 मार्ग पर अभूतपूर्व हिमपात और भीषण मौसम की स्थिति के बीच, सेना ने एक बार फिर मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया और पर्यटकों सहित फंसे हुए लोगों को समय पर सहायता प्रदान की।

एक सेना अधिकारी ने बताया कि नचलाना सेना शिविर के सैनिकों ने भारी हिमपात, सड़क अवरोध और शून्य से नीचे के तापमान के कारण उत्पन्न कई संकटकालीन स्थितियों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि एनएच-44 पर नागरिकों और पर्यटकों को ले जा रहे कई वाहन फंस गए थे, जिससे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और पुरुष पर्याप्त भोजन, पानी या चिकित्सा सहायता के बिना भीषण मौसम के संपर्क में आ गए थे।

अधिकारी ने बताया कि सेना के जवान तुरंत प्रभावित लोगों तक पहुंचे और उन्हें भोजन, पीने का पानी, गर्म चाय और आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान की, जिससे जरूरतमंद सभी लोगों की सुरक्षा और राहत सुनिश्चित हुई।

एक समानांतर अभियान में, वॉरियर्स ताइक्वांडो अकादमी के 32 मार्शल आर्ट्स कैडेट, अपने प्रशिक्षकों और अभिभावकों के साथ, अचानक और भारी हिमपात के कारण नाचलाना के पास फंस गए थे। अधिकारी ने बताया,

"भोजन, पानी या आश्रय की अनुपलब्धता के कारण, समूह को, विशेष रूप से छोटे बच्चों को, गंभीर कठिनाइयों का सामना करना

पड़ा। करुणा और पेशेवर क्षमता का परिचय देते हुए, सेना के जवानों ने उन्हें नाचलाना शिविर में पहुंचाया, जहां उन्हें गर्म भोजन, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, गर्म कपड़े और सुरक्षित आवास प्रदान किया गया, जब तक कि मौसम में सुधार नहीं हुआ और हिमपात कम नहीं हो गया।"

संगलदान रेलवे स्टेशन पर फंसे यात्रियों और स्थानीय रेलवे अधिकारियों की मदद के लिए किए गए एक आपातकालीन कॉल पर, अधिकारी ने बताया कि संगलदान आर्मी कैंप के सेना के जवानों ने शुक्रवार को भारी बर्फबारी के बीच फंसे 65 यात्रियों को आवश्यक वस्तुएं मुहैया कराईं।

यातायात विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा, मुगल रोड, सिंथन टॉप रोड, श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग और विभिन्न जिलों की दर्जनों अन्य सड़कों पर भी बर्फबारी के कारण यातायात बाधित रहा। अधिकारी

ने कहा, प्लोंगों को सलाह दी जाती है कि जब तक ये सड़कें पूरी तरह से बहाल नहीं हो जातीं और यातायात के लिए सुरक्षित घोषित नहीं हो जातीं, तब तक इन पर यात्रा न करें।

सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) भी जम्मू-राजौरी-पूंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को बहाल करने के लिए एक बड़ा बर्फ हटाने का अभियान चला रहा है।

बीआरओ के एक अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को भारी बर्फबारी के बाद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण यह राजमार्ग राजौरी के बीजी और पूंछ की जर्जर वाली गली के बीच बंद है।

उन्होंने कहा कि बीआरओ के कर्मचारी और मशीनरी सड़क को बहाल करने और यातायात के लिए खोलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

जम्मू क्षेत्र के अधिकांश पहाड़ी इलाकों में, जिनमें पटनीटॉप, नथाटॉप और भदरवाह जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शामिल हैं, शुक्रवार को मध्यम से भारी हिमपात हुआ। वहीं, जम्मू शहर समेत मैदानी इलाकों में हुई बारिश ने दो महीने से अधिक समय से चले आ रहे सूखे को समाप्त कर दिया। राजौरी कस्बे और डोडा व उधमपुर के कुछ हिस्सों जैसे जम्मू के कुछ इलाकों में एक दशक से अधिक समय बाद हिमपात हुआ।

पीएलए में बड़े पैमाने पर हुई छंटनी के दौरान अनुशासनहीनता के उल्लंघन के लिए चीन के शीर्ष सैन्य अधिकारी की जांच चल रही है



नई दिल्ली

बीजिंग : रक्षा मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि पीएलए के सर्वोच्च अधिकारी जनरल झांग यूक्सिया समेत दो वरिष्ठ चीनी सैन्य अधिकारियों के खिलाफ सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के अनुशासन और कानूनों के गंभीर उल्लंघन के आरोप में जांच शुरू की गई है।

जनरल झांग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व वाली शक्तिशाली केंद्रीय सैन्य आयोग (सीएमसी) के सर्वोच्च उपाध्यक्ष हैं।

सीएमसी में झांग की स्थिति उन्हें चीनी सेना का सर्वोच्च वर्दीधारी अधिकारी बनाती है।

जांच के दायरे में आने वाले दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जनरल लियू झेनली हैं, जो सीएमसी के सदस्य हैं और संयुक्त स्टाफ विभाग के चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। रक्षा

मंत्रालय ने एक संक्षिप्त प्रेस विज्ञापित में कहा, प्सीपीसी केंद्रीय समिति के विचार-विमर्श के बाद झांग यूक्सिया और लियू झेनली के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

उनके खिलाफ, विशेष रूप से सर्वोच्च सैन्य अधिकारी झांग के खिलाफ, इस जांच ने चीनी सैन्य प्रतिष्ठान में हलचल मचा दी है। झांग 24 सदस्यीय पोलित ब्यूरो के भी सदस्य हैं, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का सत्ता केंद्र है। 2012 में सत्ता संभालने के बाद से शी जिनपिंग द्वारा चलाए गए भ्रष्टाचार विरा. 'धी अभियान के तहत पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के दर्जनों वरिष्ठ अधिकारियों को बर्खास्त या दंडित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग कल 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाएगा

नई दिल्ली

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) कल नई दिल्ली में 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी-2026) मनाने जा रहा है। इस वर्ष इस आयोजन का विषय भेरा भारत, मेरा वोट है और इसका नारा है, भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक।

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित समारोह की अध्यक्षता करेंगी और मुख्य अतिथि होंगी। केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संघू और डॉ. विवेक जोशी के साथ कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। परंपरा के अनुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति इस कार्यक्रम को संबोधित करते हैं और नव पंजीकृत युवा मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रदान करते हैं।

माननीय राष्ट्रपति प्रभावी तकनीकी उपयोग, चुनाव प्रबंधन और व्यवस्था, अभिनव मतदाता

जागरूकता, आदर्श आचार संहिता का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण सहित विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रक्रियाओं के पुरस्कार प्रदान करते हैं, साथ ही अन्य विशेष पुरस्कार और मीडिया के लिए पुरस्कार भी देते हैं।

एनवीडी-2026 के अवसर पर दो प्रकाशनों का विमोचन भी होगा दृ 2025रु पहल और नवाचारों का वर्ष और रचना का पर्व, बिहार का गर्व, जो बिहार में आम चुनावों के सफल संचालन पर आधारित एक प्रकाशन है।

इस अवसर पर चुनाव प्रबंधन और लोकतांत्रिक विकास में चुनाव आयोग के वैश्विक नेतृत्व को दर्शाने एक वीडियो भी प्रदर्शित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में चुनाव के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष प्रदर्शनी भी होगी, जिसमें मतदाता सूची तैयार करना और चुनाव संच. लान शामिल है।

प्रदर्शनी में मतदाताओं के लाभ के लिए चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में की गई पहलों और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के सफल संचालन पर भी प्रकाश डाला जाएगा।

कश्मीर के आईजीपी ने कहा कि घाटी में गणतंत्र दिवस समारोह को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : कश्मीर पुलिस प्रमुख वीके बर्डी ने शनिवार को कहा कि घाटी में शांतिपूर्ण गणतंत्र दिवस समारोह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। घ्युलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) बर्डी कश्मीर में मुख्य गणतंत्र दिवस कार्यक्रम स्थल बख्शी स्टेडियम में पूर्ण-नग्न पूर्वाभ्यास के बाद मीडियाकर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर दिन भर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। बर्डी ने

कहा, हमने जम्मू-कश्मीर पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भागीदारी के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की है। उन्होंने आगे कहा कि मुख्य कार्यक्रम के अलावा, घाटी के विभिन्न जिला मुख्यालयों में अलग-अलग



कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आईजीपी ने कहा कि शांतिपूर्ण और सुचारु समारोह सुनिश्चित करने के लिए घाटी भर में इसी तरह की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और लोगों से समारोह में शामिल होने की अपील की। घ्यउन्होंने कहा, ध्याम लोगों का अपने परिवार. के साथ समारोह में शामिल होने के लिए

हार्दिक स्वागत है। स्कूली बच्चों को भी शामिल होना चाहिए। यह एक खुला कार्यक्रम है और हर कोई आने के लिए स्वतंत्र है। कश्मीर संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग की अध्यक्षता में बख्शी स्टेडियम में पूर्ण वेशभूषा पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट में सलामी ली। उन्होंने यह भी बताया कि गर्ग ने इस अवसर पर परेड का निरीक्षण किया। पुलिस और विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट में भाग लिया, जिसम.

कई वरिष्ठ नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारी पूर्वाभ्यास के दौरान उपस्थित थे।

अधिकारियों के अनुसार, सुरक्षा बलों ने एहतियात के तौर पर कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाली सड़कों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी थी और कार्यक्रम समाप्त होने तक किसी भी वाहन को चलने की अनुमति नहीं

गणतंत्र दिवस समारोह से झलकी जम्मू-कश्मीर की एकता, विकास और नई उम्मीदें : सतीश शर्मा



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, परिवहन, युवा सेवा एवं खेल, आईटी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सतीश शर्मा ने जम्मू-कश्मीर की जनता को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने स्पोर्ट्स स्टेडियम कठुआ में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च-पास्ट की

सलामी ली।

अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के मूल्यों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है।

उन्होंने बताया कि तिरंगा देश की एकता, साहस और शांति का प्रतीक है।

मंत्री ने जम्मू-कश्मीर के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शांति बनाए

रखने के लिए सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में प्रदेश में शांति, विकास और जनकल्याण को प्राथमिकता दी जा रही है।

सतीश शर्मा ने बताया कि समग्र कृषि विकास कार्यक्रम से किसानों की आय बढ़ी है और कठुआ जिला कृषि में अग्रणी बनकर उभरा है।

उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा, पेयजल, आवास, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की योजनाओं की भी जानकारी दी।

मंत्री ने नशे के खिलाफ सरकार की सख्त नीति का उल्लेख करते हुए कहा कि युवाओं को इस बुराई से बचना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

कार्यक्रम में स्कूली छात्रों ने देशभक्ति

सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान शहीद परिवारों, मेधावी छात्रों और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाला को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर डीडीसी चेरमैन कर्नल (सेवानिवृत्त) महान सिंह, विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण, उपायुक्त कठुआ राजेश शर्मा, एसएसपी मोहिता शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

गणतंत्र दिवस परेड : कर्तव्य पथ पर दिखेगा समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जनभागीदारी के साथ 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष और देश की प्रगति व सैन्य शक्ति का अनोखा संगम

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : कृतज्ञ राष्ट्र 26 जनवरी, 2026 को 77वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से समारोह का नेतृत्व करेंगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष श्री एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष सुश्री उर्सुला वॉन डेर लेयेन इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। इस वर्ष का समारोह देखने लायक होगा क्योंकि राष्ट्रपति भवन से लेकर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक तक फैला कर्तव्य पथ, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत की अभूतपूर्व प्रगति, मजबूत सैन्य शक्ति, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की भागीदारी के अविस्मरणीय संगम को प्रस्तुत करने के लिए पूरी तरह से सजाया गया है।

परेड

समारोह सुबह साढ़े दस बजे शुरू होगा और लगभग 90 मिनट तक चलेगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के दौरे से होगी, जहां वे माल्यार्पण करके प्राणोत्सर्ग करने वाले राष्ट्र नायकों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति परेड देखने के लिए कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर जाएंगे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष का आगमन 'पारंपरिक बग्गी' में होगा। उसके साथ राष्ट्रपति के अंगरक्षक होंगे जो भारतीय सेना की सबसे वरिष्ठ रेजिमेंट है। परंपरा के अनुसार, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रगान होगा और 105 उड़ लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। यह देश में बना तोपखाना हथियार सिस्टम है। 172 फील्ड रेजिमेंट की 1721 सेरेमो. नियल बैटरी 21 तोपों की सलामी देगी।

विविधता में एकता थीम पर 100 सांस्कृतिक कलाकार परेड की शुरुआत करेंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का शानदार प्रदर्शन होगा। यह देश की एकता और समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को दिखाएगा। 129 हेलीकॉप्टर यूनिट के चार डप-17 1ट हेलीकॉप्टर ध्वज फॉर्मेशन में फूलों की पंखुड़ियों की बारिश करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को लेकर, हेलीकॉप्टरों के इस फॉर्मेशन का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन आलोक अहलावत करेंगे।

इसके बाद राष्ट्रपति के सलामी लेने के साथ परेड

शुरू होगी। दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार परेड की कमान संभालेंगे। जो दूसरी पीढ़ी के अधिकारी हैं, मुख्यालय दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल नवराज ढिल्लों परेड के सेकंड-इन-कमांड होंगे जो तीसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी हैं।

इसके बाद सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गर्वित विज. ता आएंगे। इनमें परमवीर चक्र विजेता — सूबेदार मेजर (मानद कैप्टन) योगेंद्र सिंह यादव (रिटायर्ड) और सूबेदार मेजर संजय कुमार — और अशोक चक्र विजेता — मेजर जनरल सीए पिथावालिया (रिटायर्ड) और कर्नल डी श्रीराम कुमार शामिल हैं। परमवीर चक्र दुश्मन के सामने रक्षा बलों के सदस्यों की सबसे अधिक असाधारण बहादुरी, वीरता और आत्म-बलिदान के कार्य के लिए दिया जाता है, जबकि अशोक चक्र अन्य स्थितियों में किए गए इसी तरह के वीरता, साहस और आत्म-बलिदान के कार्यों के लिए दिया जाता है।

यूरोपियन यूनियन दल
यूरोपियन यूनियन (ईयू) दल में तीन जिप्सी पर चार ध्वजवाहक होंगे। वे चार ध्वज ले जाते हुए दिखेंगे। इनमें ईयू का ध्वज होगा, जो यूरोपियन यूनियन का सबसे पहचाना जाने वाला प्रतीक है; इनमें यूरोपियन यूनियन मिलिट्री स्टाफ का ध्वज; ईयू नेवल फोर्स अटलांटा का झंडा; और ईयू नेवल फोर्स एस्पाइड्स का झंडा शामिल होगा।

सेना दल

पहली बार परेड में भारतीय सेना का चरणबद्ध बैटल एरे फॉर्मेट दिखाया जाएगा, जिसमें हवाई घटक भी शामिल होगा। रेकी एलिमेंट में 61 कैवलरी एक्टिव कॉम्बैट यूनिट्स में होगी। इसके बाद हाई मोबिलिटी रिकोनिसेंस व्हीकल होगा, जो भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है। हवाई सहायता स्वदेशी ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर और इसका आर्मर्ड वर्जन रुद्र प्रहार फॉर्मेशन देगा, जो युद्धक्षेत्र में निर्णायक पहल का प्रदर्शन करेगा।

इसके बाद कॉम्बैट एलिमेंट्स आएंगे, जिसमें ज-90 भीष्म और मेन बैटल टैंक अर्जुन सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। अपाचे 1-64 और प्रचंड लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से इन्हें हवाई सहायता मिलेगी। अन्य मैकेनाइज्ड कॉलम में टडच-ए इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल, साथ में नाग मिसाइल सिस्टम (ट्रैक) डा-2 शामिल हैं। इसके बाद स्पेशल फोर्स की टुकड़ी

होगी, जिसमें अजयकेतु ऑल-टेरेन व्हीकल, रणध्वज रण्ड टेरेन टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ध्वंशक लाइट स्ट्राइक व्हीकल शामिल होंगे। इनके बाद वाहनों पर लगे रोबोटिक डॉग, मानवरहित ग्राउंड व्हीकल और चार ऑटोनोंस मानवरहित ग्राउंड व्हीकल (निग्रह, भैरव, भुविर्क्षा और कृष्णा) नजर आएंगे। कॉम्बैट सपोर्ट एलिमेंट में भारत की नई पीढ़ी के मानवरहित वॉरहेड हथियार शामिल होंगे। उन्हें शक्तिबाण और दिव्यास्त्र के जरिए दिखाया जाएगा, जो खास हाई मोबिलिटी व्हीकल्स (व्हेट 6+6) पर लगे होंगे। अत्याधुनिक तकनीकों से लैस, ये एक साथ झुंड में ड्रोन, टेथर्ड ड्रोन सिस्टम और स्वदेशी रूप से विकसित टैक्टिकल हाइब्रिड नॉट जोल्ट के जरिए एडवांस्ड सर्विलांस दिखाते हैं। इनका इस्तेमाल तोपखाने की फायरिंग को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। लक्ष्य भेदने की इनकी क्षमता को हवाई लोडिंगरिंग म्यूनिशन की बड़ी रेंज — भालू, मिनी हार्पी, पीसकीपर, जै (एक्सटेंडेड रेंज), जै (मीडियम रेंज), और स्काई स्ट्राइकर — से मजबूत किया गया है, जो युद्ध के मैदान में गहन और सटीक हमला करने में मदद करते हैं। ये सिस्टम झुंड वाले ड्रोन, 1,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले लॉन्ग रेंज ड्रोन को देखने और हमला करने के मिशन के लिए, और महत्वपूर्ण टारगेट पर सटीक हमले के लिए लोडिंगरिंग म्यूनिशन लॉन्च करने में सक्षम हैं।

इसके बाद धनुष गन सिस्टम और अमोघ एडवांस्ड टोएड आर्टिलरी गन सिस्टम (जल्लू) आएंगे, जो आत्मनिर्भर भारत की भावना और रक्षा निर्माण में तकनीकी आत्मनिर्भरता को दिखाएंगे। लॉन्ग-रेंज सटीकता और जबरदस्त मारक क्षमता का शक्तिशाली संयोग सुपरसोनिक ब्रह्मोस वेपन सिस्टम के साथ-साथ स्वदेशी सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के जरिए दिखाया जाएगा, जो एक साथ डीप स्ट्राइक डोमिनेंस दिखाएंगे।

आकाश वेपन सिस्टम और अग्र मीडियम रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (ड्रैग) सिस्टम भी सलामी मंच के सामने से गुजरेंगे। ये भारत की वायु रक्षा के दो मजबूत स्तंभ हैं। इसके बाद ड्रोन शक्ति लॉरी आएगी, जिसे कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स ने अग्रिम इलाकों में भारतीय सेना की ऑपरेशनल क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया है। ग्लास केस वाला इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल सेंटर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगा जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को संक्षेप में दिखाया गया है।

श्विरासत, विविधता और विकास के शानदार संगम के कारण यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जादुई उपाय साबित हुआ। एक तरफ ब्रह्मोस मिसाइल ने दुश्मन को घातक चोट पहुंचाई, वहीं आकाश मिसाइल सिस्टम और 400 ने सुरक्षा कवच प्रदान किया, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुदर्शन चक्र विजन को दर्शाता है। इसके बाद रक्षा बलों के हिम योद्धा आएंगे, जिनमें एनिमल कंटेजेंट शामिल है। इसमें बहादुर सैनिकों के साथ बैक्टीरियन ऊंट, जांस्कर टट्टू, ब्लैक काइट्स (शिकारी पक्षी) — बुद्धिमान और सतर्क पक्षी; और भारतीय नस्ल के कुत्ते (मुधोल हाउंड, रामपुर हाउंड, चिप्पीपराई, कोम्बई और राजापलाम) बुलेट-प्रूफ जैकेट, कैमरे, लैप, रेडियो और उन्नत निगरानी प्रणालियों से लैस होंगे। एक वाहन पर लगा रलेशियर जट भी हिम योद्धाओं का हिस्सा है।

कर्तव्य पथ पर मार्च करते हुए मिक्सड स्काउट्स कंटेजेंट; राजपूत रेजिमेंट; असम रेजिमेंट; जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री; रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी; 4 भैरव बटालियन दृ सिख लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट; और संयुक्त सैन्य बैंड भी दिखाई देंगे।

नौसेना दल

नौसेना के दल में 144 युवा कर्मी शामिल होंगे, जिसका नेतृत्व लेफ्टिनेंट करण नाग्याल दल कमांडर के रूप में करेंगे, और लेफ्टिनेंट पवन कुमार गांधी, लेफ्टिनेंट प्रीति कुमारी और लेफ्टिनेंट वरुण ड्रेवरिया प्लाटून कमांडर होंगे।

इसके बाद नौसेना की झांकी होगी, जो मजबूत राष्ट्र के लिए मजबूत नौसेना की थीम का सजीव चित्रण प्रस्तुत करेगी। झांकी में 5वीं शताब्दी ईस्वी जहाज दिखाया गया है जिसे किलों के बजाय नारियल की रस्सी से सिला जाता है। इसे अब फ्लैट कौडिन्य नाम दिया गया है। मराठा नौसेना के गुरब श्रेणी के जहाज, और फ्रंटलाइन स्वदेशी प्लेटफॉर्म भी दिखाए जाएंगे, जिसमें विमानवाहक पोत फ्लैट कौडिन्य, प्रोजेक्ट 17। नीलगिरि-श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट फ्लैट हिमगिरि और फ्लैट उदयगिरि, एक कलवरी-श्रेणी की पनडुब्बी, और GSAT-7R (प्रोजेक्ट रोहिणी) संचार उपग्रह शामिल हैं। झांकी में फ्लैट तारिणी द्वारा नविका सागर परिक्रमा-ए अभियान के हिस्से के रूप में अपनाए गए विश्व भ्रमण मार्ग का चित्रण भी दिखाया गया है। नौसेना कर्मियों के अलावा, सी कैडेट्स कोर के युवा कैडेट झांकी के साथ मार्च करेंगे। यह मुंबई में युवाओं को बुनियादी समुद्री कौशल सिखाने वाला गैर-सरकारी संगठन है।

भारत की राष्ट्रपति ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शिरकत की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने आज (25 जनवरी, 2026) नई दिल्ली में आयोजित 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित किया।

समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की ताकत महज मतदाताओं की विशाल संख्या में ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भावना की गहराई में भी निहित है। इस प्रक्रिया में यहां तक कि सबसे बुजुर्ग मतदाता, दिव्यांग मतदाता और दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोग भी अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। उन्होंने जागरूक मतदाताओं और चुनाव आयोग के नेतृत्व में चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों की सराहना की, जिन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने के इतने प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं।

राष्ट्रपति ने कहा कि जनभागीदारी जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की भावना को व्यावहारिक रूप देती है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने के मकसद से कई प्रयास किए हैं कि इस अधिकार को प्रयोग करने से कोई भी मतदाता पीछे न छूटे।



मतदाताओं में जागरूकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा इस वर्ष चुना गया विषय, 'भेरा भारत, मेरा वोट' भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में भारतीय नागरिक, हमारे लोकतंत्र की भावना को दर्शाता है और हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है।

राष्ट्रपति ने कहा कि मतदान केवल एक राजनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है। यह

चुनावों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों के विश्वास का प्रतिबिंब है। यह नागरिकों के लिए अपनी आकांक्षाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम भी है। बिना किसी भेदभाव के सभी वयस्क नागरिकों को मिला मतदान का अधिकार, राजनीतिक और सामाजिक न्याय और समानता के हमारे संवैधानिक आदर्शों को मूर्त रूप देता है। हमारे संविधान में निहित एक व्यक्ति, एक वोट प्रणाली हमारे संविधान निर्माताओं के

आम जनता की बुद्धिमत्ता में दृढ़ विश्वास का परिणाम थी।

हमारे देश के मतदाताओं ने उनके विश्वास को सही साबित किया है और भारतीय लोकतंत्र ने विश्व मंच पर एक असाधारण उदाहरण के रूप में सम्मान अर्जित किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि मतदान का अधिकार अहम है, लेकिन यह भी उतना ही ज़रूरी है कि सभी वयस्क नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए अपने

मताधिकार का प्रयोग करें। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी मतदाता, प्रलोभन, अज्ञानता, गलत सूचना, दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह से मुक्त होकर, अपनी अंतःराष्ट्र की शक्ति से हमारी चुनावी प्रणाली को मजबूत करेंगे।

राष्ट्रपति ने देश भर के उन सभी युवा मतदाताओं को बधाई दी, जिन्हें उनके मतदाता पहचान पत्र मिल चुके हैं और कहा कि यह कार्ड उन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र में सक्रिय रूप से भाग लेने का अमूल्य अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आज के मतदाता भारत के भविष्य के निर्माता हैं। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि देश के सभी युवा मतदाता जिम्मेदारी से अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करेंगे और राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे।

वर्ष 2011 से, भारत निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस आयोजन का मकसद मतदाता की अहमियत पर फोकस करना, नागरिकों में चुनावों को लेकर जागरूकता बढ़ाना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रेरित करना है।

पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बसोहली में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस



सबका जम्मू कश्मीर

बसोहली, जम्मू-कश्मीर: पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, बसोहली में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और

देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती अर्चना शर्मा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय गान गाया गया। इस अवसर पर एनसीसी

कैडेट्स, विद्यालय बैंड और विभिन्न हाउसों के विद्यार्थियों ने अनुशासित और आकर्षक परेड प्रस्तुत की। विद्यालय बैंड की देशभक्ति धुनों से पूरा परिसर देशभक्ति के रंग में रंग गया। कार्यक्रम के दौरान

विद्यार्थियों ने देशभक्ति गीत, नृत्य और भाषण प्रस्तुत किए, जिनमें भारत की सांस्कृतिक विरासत और लोकतांत्रिक मूल्यों को दर्शाया गया। इन प्रस्तुतियों की सभी उपस्थित शिक्षक एवं विद्यार्थियों ने सराहना

की। कार्यक्रम में शिक्षक और विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रही। संपूर्ण आयोजन ने संविधान के आदर्शों और देशप्रेम की भावना को और अधिक मजबूत किया। कार्यक्रम का समापन गरिमामय वातावरण में हुआ।

भारतीय सेना द्वारा स्वर्गीय लांस नायक कुलबीर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई।



सबका जम्मू कश्मीर

नौशहरा 28 जनवरी 2026 स्वर्गीय लांस नायक कुलबीर सिंह के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानित करने के लिए एक पुष्पांजलि समारोह पूरे सम्मान के साथ आयोजित किया गया, जिन्होंने देश की सेवा करते हुए कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस समारोह में स्थानीय लोग



और पूर्व सैनिक शामिल हुए, जिन्होंने शहीद वीर को श्रद्धांजलि दी। राजपूताना राइफल्स की 25वीं बटालियन के सैनिकों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सम्मान और याद के प्रतीक के रूप में पुष्प अर्पित किए गए और एक मिनट का मौन रखा गया। यह समारोह सशस्त्र बलों के उस सैनिक के प्रति गहरे गर्व, सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है जिसने साहस, निस्वार्थ सेवा और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का उदाहरण पेश



किया। स्वर्गीय लांस नायक कुलबीर सिंह का बलिदान भारतीय सेना की सर्वोच्च परंपराओं का प्रमाण है और यह साथी सैनिकों और नागरिकों के लिए एक स्थायी प्रेरणा है। राष्ट्र उनके शौर्य और प्रतिबद्धता का ऋणी रहेगा। सशस्त्र बल शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और भारतीय सेना के मूल्यों और आदर्शों को बनाए रखने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हैं।

साप्ताहिक राशिफल



मेप

मेप राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी जीवन से लेकर करियर-कारोबार तक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।



वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल-मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटक कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर-परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी-साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।



मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक-कार्यों में खूब रहेगा। किसी धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. बले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।



कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।



सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुनी पड़ सकती है।



कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद-विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।



तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते-नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।



वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता-सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन-पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।



धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता है। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।



मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आए अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।



कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।



मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी-रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।

केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डुम्बूर में 450 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा दौरे के अंतिम दिन आज डुम्बूर झील के नारकेल कुंजा में 450 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे श्माताबारी पर्यटन सर्किट की आधारशिला रखी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा कार्यक्रम में वर्युअल माध्यम से शामिल हुए, जबकि पर्यटन मंत्री सुशांत चौधरी कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित थे। इस आधारशिला समारोह के साथ, केंद्रीय मंत्री ने अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान त्रिपुरा के लिए कुल 750 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा की। श्री सिंधिया ने कहा कि माताबारी पर्यटन सर्किट आध्यात्मिकता, प्रकृति और आजीविका का संगम बनेगा।

केंद्रीय मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि 450 करोड़ रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा माताबारी पर्यटन सर्किट, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, छबीमुरा और डुम्बूर झील को एकीकृत करेगा, जिससे त्रिपुरा आध्यात्मिक और पर्यावरण-पर्यटन के वैश्विक मानचित्र पर प्रमुख स्थान प्राप्त करेगा। परियोजना की कुल लागत में से 276 करोड़ रुपये पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा दिए जा रहे हैं। इस परियोजना में तैरते हुए घाट, पर्यावरण के अनुकूल रिसॉर्ट, आधुनिक पर्यटन सुविधाएं और स्थानीय संस्कृति में रचे-बसे अनुभव शामिल होंगे, जिससे दुर्बु क्षेत्र को एक विशिष्ट अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पहचान मिलेगी।

भविष्य की आजीविका की नींव रखी गई है। श्री सिंधिया



श्री सिंधिया ने कहा कि यह त्रिपुरा के इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा, "आज हमने केवल पत्थर नहीं रखे हैं; हमने भविष्य की आजीविका की नींव रखी है।" माताबारी पर्यटन सर्किट से 4,000-5,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है, जिसमें लगभग 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होगी। स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय युवाओं को पर्यटन संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे के विकास पर बल्कि मानव संसाधन विकास पर भी ध्यान केंद्रित करेगी, जिसके अंतर्गत प्रमुख संस्थानों में दूर गाइडों को प्रशिक्षित किया जाएगा। दुर्बु झील की प्राकृतिक भव्यता और

त्रिपुरा का गर्मजोशी भरा आतिथ्य सत्कार

केंद्रीय मंत्री ने दुर्बु झील की निर्मल सुंदरता, इसके शांत जल, हरे-भरे द्वीपों और निर्मल वातावरण की प्रशंसा करते हुए इसे प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक दुर्लभ संगम बताया। उन्होंने त्रिपुरा के लोगों के स्नेह, सादगी और आतिथ्य सत्कार को राज्य की सबसे बड़ी शक्ति बताते हुए कहा कि ये गुण त्रिपुरा को एक वैश्विक पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने में सहायक होंगे। उन्होंने कहा, त्रिपुरा एक ऐसा खजाना है जिसे दुनिया के सामने प्रदर्शित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में त्रिपुरा का परिवर्तन श्री सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के श्विकसित पूर्वोत्तर, स्थानीय से वैश्विक और

एक्ट ईस्ट पॉलिसी के दृष्टिकोण के अंतर्गत त्रिपुरा को दक्षिण-पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में विकसित किया जा रहा है।

उन्होंने मुख्यमंत्री माणिक साहा के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र-राज्य के मजबूत समन्वय ने त्रिपुरा को विकास की नई ऊंचाइयों को छूने में सक्षम बनाया है।

तीन दिवसीय यात्रा के दौरान 565 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की घोषणा

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री ने अपने दौरे के पहले दिन, सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सौर माइक्रोग्रिड सहित विभिन्न क्षेत्रों में 220 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। दूसरे दिन, उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों से सीधा संपर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 80 करोड़ रुपये की अगरबुड मूल्य श्रृंखला परियोजना का शिलान्यास किया। श्री सिंधिया ने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले वर्षों में, त्रिपुरा पर्यटन, अगरबुड, बांस और अवसंरचना विकास के माध्यम से आत्मनिर्भर राज्य के रूप में उभरेगा और पूर्वोत्तर भारत के विकास का एक मजबूत स्तंभ बनेगा।

पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने के लिए शरीन गोल्लखर पहल

केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि पूर्वोत्तर में कृत्रिम बांस को बढ़ावा देने के लिए 22 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। शरीन गोल्लखर नामक यह पहल क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ विकास को भी बढ़ावा देगी।



Helpline

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहु	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिममत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे प्लेटफार्म	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर

गांधी नगर

कंपनी बाग

नया प्लॉट

पंजतीर्थ

दूरसंचार विभाग

डायरेक्टरी प्लेटफार्म

फॉल्ट रिपेयर

ट्रंक बुकिंग

बिलिंग शिकायत

जम्मू नगर पालिका

जं. लाइन्स

प्रशासन अधिकारी

स्वास्थ्य अधिकारी

डाक सेवाएँ

मुख्य डाकघर शहर

गांधी नगर

अग्निशमन सेवाएँ

नियंत्रण कक्ष

शहर

गांधी नगर

नहर

गंग्याल

रसोई गैस डीलर

चिनाब गैस

गुलमौर गैस

जैकफेड

एचपी गैस

शिवांगी गैस

तवी गैस

पावर हाउस

गांधी नगर

नहर रोड

जानीपुर

नानक नगर

परैड

2543557

2430786

2542582

2573429

2547537

सतवारी कैंट

अस्पताल

जीएमसी अस्पताल

एस.एम.जी.एस. अस्पताल

सी.डी. अस्पताल

डेंटल अस्पताल

गांधी नगर अस्पताल

सरवाल अस्पताल

जी.बी. पंत कैंट अस्पताल

आयुर्वेदिक कॉलेज

सी.आर.पी. अस्पताल

आचार्य श्री चंदर

मानसिक अस्पताल

स्वामी विवेकानंद

ब्लड बैंक

एम्बुलेंस

एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)

नर्सिंग होम

मदन अस्पताल

मेडिकेयर

त्रिवेणी नर्सिंग होम

सुविधा नर्सिंग होम

अल. फिरदौस नर्सिंग होम

आस्था नर्सिंग होम

बी एन चौरिटेबल ट्रस्ट

चोपड़ा नर्सिंग होम

हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल

जीवन ज्योति

युद्धवीर नर्सिंग होम

मीडियाएड नर्सिंग होम

सीता नर्सिंग होम

विभूति नर्सिंग होम

रामेश्वर नर्सिंग होम

बी एन चौरिटेबल

महर्षि दयानंद

2452813

2584290

2547635

2577064

2544670

2430041

2579402

2433500

2543661

2591105

2662536

2577444

2547418

2547637

2584225, 2575364

2543739

2456727

2435070

2452664

2555965

2545050

2576707

2505310

2573580

2541952

2576985

2547821

2466744

2435007

2547969

2580601

2555631

2545225

मनरेगा बचाओ संग्राम : ठाकुर बलवीर सिंह और सतीश शर्मा का केंद्र सरकार पर तीखा हमला



सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ऊधमपुर जिले के रामनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चौकी चंद्रोड़ में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर मनरेगा जैसी जनकल्याणकारी योजना को कमजोर करने का गंभीर आरोप लगाया।

सभा को पूर्व विधायक ठाकुर बलवीर सिंह, पूर्व चेयरमैन नगर निगम जम्मू एवं जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के महासचिव सतीश शर्मा, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मंगोत्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा, गांव चौकी चंद्रोड़ के सरपंच सुनील शर्मा तथा शंभू कुमार ने संबोधित किया।

पूर्व विधायक ठाकुर बलवीर सिंह ने कहा कि मनरेगा देश के गरीब और ग्रामीण मजदूरों के लिए जीवनरेखा है, लेकिन केंद्र सरकार की नई नीतियों और नियमों ने इस योजना को लगभग निष्क्रिय कर दिया है।

उन्होंने कहा, "मनरेगा मजदूरों का कानूनी अधिकार है, लेकिन नए कानूनों, ऑनलाइन

प्रक्रियाओं और तकनीकी शर्तों के जरिए गरीब मजदूरों को योजना से बाहर किया जा रहा है। मजदूरी का भुगतान महीनों तक रोका जा रहा है, जिससे मजदूरों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति पैदा हो रही है।"

उन्होंने मनरेगा के बजट में की जा रही कटौती पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर इसका बजट घटा रही है, ताकि ग्रामीणों को मजबूर होकर रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करना पड़े।

कांग्रेस महासचिव सतीश शर्मा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मनरेगा के नाम पर लाए गए नए नियम वास्तव में इस योजना को खत्म करने की साजिश हैं।

उन्होंने कहा, "काम पूरा होने के बावजूद मजदूरों को समय पर मेहनताना नहीं मिल रहा। तकनीकी खामियों और ऑनलाइन अप्रुवल के नाम पर भुगतान रोका जा रहा है। यह सीधे तौर पर गरीब मजदूर के हक पर हमला है।"

सतीश शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और बेरा.

जगारी लगातार बढ़ती जा रही है।

जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुमित मंगोत्रा ने कहा कि मनरेगा को कमजोर करना भाजपा की गरीब विरोधी सोच को उजागर करता है।

उन्होंने कहा, "ग्रामीण मजदूर महीनों से अपनी मजदूरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी सड़कों से लेकर संसद तक मजदूरों की आवाज बुलंद करेगी।"

पूर्व जिला अध्यक्ष विनोद शर्मा ने कहा कि मनरेगा में पारदर्शिता की बात करने वाली सरकार जमीनी सच्चाई से पूरी तरह मुंह मोड़ चुकी है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ग्राम सभाओं और सोशल ऑडिट को कमजोर कर मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है।

गांव चौकी चंद्रोड़ के सरपंच सुनील शर्मा और शंभू कुमार ने कहा कि मनरेगा मजदूरों को कई-कई महीनों तक मजदूरी का भुगतान नहीं मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परिवार कर्ज में डूबते जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि गांवों में काम की भारी कमी है और प्रशासन की उदासीनता से हालात दिन-प्रतिदिन और खराब होते जा रहे हैं। सभी वक्ताओं ने ग्रामीणों से आह्वान किया कि वे अपने अधिकारों के लिए एकजुट हों और मनरेगा बचाओ संग्राम को एक मजबूत जन आंदोलन बनाएं।

नेताओं ने दोहराया कि कांग्रेस पार्टी गरीबों, मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण, कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे।

भारतीय रेसिंग सनसनी अतिका मीर ने वर्ल्ड कार्टिंग चैंपियन मोडेना के साथ 2026 डब्ल्यूएसके के लिए ड्राइव हासिल की

ला कोंका (इटली)

भारतीय रेसिंग प्रतिभा अतिका मीर ने प्रतिष्ठित 'ज़' चैंपियनशिप के 2026 सीज़न के लिए मौजूदा विश्व चैंपियन मोडेना रेसिंग टीम में जगह पक्की कर ली है। 'ज़' को कार्टिंग का शॉर्टमूला 1२ माना जाता है। महज 11 वर्षीय अतिका घन्ने इस सीज़न में अत्यधिक प्रतिस्पर्धी जूनियर श्रेणी (12-14 वर्ष) में भाग लेकर शीर्ष तक पहुंचने का कठिन रास्ता चुना है। पिछले साल मिनी श्रेणी (8-12 वर्ष) में उनके प्रभावशाली प्रदर्शन के दम पर, फॉर्मूला 1 अकादमी द्वारा समर्थित इस ड्राइवर को पूरे सीज़न के लिए अनुबंधित किया गया है और वह 'ज़' सुपर मास्टर सीरीज़, 'ज़' यूरो सीरीज़, 'ज़' फाइनल कप और अन्य चैंपियनशिप में भाग लेंगी।

इस प्रक्रिया में, अतिका घन्ने में क्लबश्र श्रेणी में ड्राइव करने वाली पहली भारतीय महिला बनेंगी और उल्लेखनीय रूप से 37 विश्व स्तरीय ड्राइव. रॉ की पूरी ग्रिड में एकमात्र महिला होंगी। 'ज़' सीरीज़ कार्टिंग का उच्चतम स्तर है जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ ड्राइविंग प्रतिभाओं के साथ-साथ अग्रणी कार्ट और इंजन निर्माताओं को आकर्षित करता है। डब्ल्यूएसके सीरीज़ का उद्देश्य युवा ड्राइवरों को रेसिंग कौशल, तकनीकी ज्ञान और मोटरस्पोर्ट की समझ विकसित करने के लिए एक मंच प्रदान करके उनका विकास करना है। लुईस हैमिल्टन, मैक्स वस्टापेन और सेबेस्टियन वेटेल जैसे फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन अपने शुरुआती वर्षों

में डब्ल्यूएसके में रेस कर चुके हैं।

मिनी कैटेगरी से ओकेएनजे जूनियर कैटेगरी में आना अतिका घन्ने लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन वह इस चुनौती के लिए तैयार हैं। 10 बीएचपी इंजन से लेकर 29 बीएचपी इंजन तक, 126 किमी प्रति घंटे की रफ्तार और 2.5 से अधिक जी फोर्स वाले बड़े कार्टर्स के साथ, अतिका घन्ने शारीरिक क्षमता और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों के खिलाफ होगी। अतिका घन्ने कहा, "मैं बहुत उत्साहित हूं और मोडेना द्वारा मुझे साइन करने के लिए आभारी हूं। इस श्रेणी में इतनी प्रतिष्ठित टीम और मौजूदा विश्व चैंपियनों के साथ जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मेरी परीक्षा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ड्राइवरों के खिलाफ होगी और मैं इस चुनौती के लिए तैयार हूं। डब्ल्यूएसके में ग्रिड बहुत करीबी हैं और ड्राइविंग का स्तर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। मुझे उम्मीद है कि मैं उनसे सीखूंगी और खुद को बेहतर बनाऊंगी।" अतिका घन्ने पिता आसिफ मीर, जो भारत के पहले राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन हैं, ने कहा कि उन्हें जूनियर वर्ग में सीधे उतारना एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय था। उन्होंने कहा,

"हम अतिका घन्ने को सीधे मुश्किल चुनौती में डाल रहे हैं। यह उसके विकास के लिए सबसे अच्छा है। वह आसानी से मिनी कार्टिंग में रहकर रेस और चैंपियनशिप जीत सकती थी, लेकिन हमारा लक्ष्य फॉर्मूला 1 है और एक ड्राइवर के रूप में उसका विकास सर्वोपरि है।

आईसीसी ने बीसीबी को सूचित किया है कि टी20 विश्व कप में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है



सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) को आधिका. रिक तौर पर सूचित कर दिया है कि आगामी टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड को उनकी जगह भेजा गया है। यह सूचना मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुर्खा चिंताआ. का हवाला देते हुए भारत आने से इनकार करने के बाद दी गई है। जानकारी के अनुसार, आईसीसी के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें अध्यक्ष

निर्वाचन आयोग ने 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026 के अवसर पर "2025 : पहल और नवाचारों का वर्ष" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : नई दिल्ली में आज 16वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस (एनवीडी2026) उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम "मेरा भारत, मेरा वोट" रखी गई, जबकि इसका नारा "भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक" था। इस अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह की अध्यक्षता माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। कार्यक्रम में केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अर्जुन राम मेघवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

इस कार्यक्रम का नेतृत्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने किया। उनके साथ चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी मंचासीन रहे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का उद्देश्य नागरिकों, विशेषकर युवाओं, को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना तथा मताधिकार के महत्व को रेखांकित करना रहा।

इस अवसर पर "2025रू पहल और नवाचारों का वर्ष" शीर्षक से एक विशेष प्रकाशन का विमोचन किया गया। इस प्रकाशन की पहली प्रति केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा माननीय राष्ट्रपति को भेंट की गई। यह पुस्तक वर्ष 2025 के दौरान चुनाव आयोग द्वारा किए गए 30 से अधिक महत्वपूर्ण प्रयासों, सुधारों और नवाचारों का दस्तावेजीकरण करती है, जिनका उद्देश्य देश की चुनावी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी तथा समावेशी बनाना रहा।

प्रकाशन में मतदाता सूची के सुदृढ़ीकरण, चुनाव संचालन में सुधार, चुनावी प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग, क्षमता निर्माण, राजनी. तिक दलों के साथ सक्रिय सहभागिता तथा भारत द्वारा अंतरराष्ट्रीय आईडीईए की अध्यक्षता संभालने जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रमुख कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।

यह दर्शाता है कि किस प्रकार चुनाव आयोग ने नवाचार और सुधारों के माध्यम से लोकतंत्र को और मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए।

इसके अतिरिक्त, पुस्तक में वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक संपन्न हुए प्रमुख चुनावों का संक्षिप्त विवरण भी दिया गया है। इनमें उपराष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव शामिल हैं। साथ ही, वैश्विक स्तर पर चुनावी सुशासन को आगे बढ़ाने में चुनाव आयोग की सक्रिय भूमिका और नेतृत्व पर भी प्रकाश डाला गया है।

आधिकारिक रूप से जवाब नहीं दिया, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।" सूत्र ने आगे कहा,

"बीसीबी ने वैश्विक संस्था को आधिकारिक रूप से सूचित करने से पहले ढाका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। उन्हें स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उन्हें बदला जा रहा है।" बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल ने आईसीसी द्वारा बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं क्रिकेट स्कॉटलैंड का कहना है कि उन्हें अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्हें जल्द ही सूचना मिल जाएगी।

स्कॉटलैंड अपने चार ग्रुप लीग मैच वेस्ट इंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में खेलेगा, जिसके बाद 17 फरवरी को मुंबई में नेपाल के खिलाफ एक मैच होगा।

डोगरी साहित्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले यशपाल निर्मल को “जम्मू-कश्मीर शासन पुरस्कार 2026”

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर के प्रसिद्ध डोगरी साहित्यकार, बाल साहित्यकार, अनुवादक और सांस्कृतिक कर्मी यशपाल निर्मल को डोगरी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए “जम्मू-कश्मीर शासन पुरस्कार 2026” से सम्मानित किया गया है।

यशपाल निर्मल डोगरी भाषा और साहित्य के सशक्त समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने अपने लेखन, अनुवाद और सामाजिक-साहित्यिक गतिविधियों के माध्यम से डोगरी भाषा को नई पहचान दिलाई है। उन्होंने डोगरी सहित विभिन्न भाषाओं में 90 से अधिक पुस्तकों का लेखन और प्रकाशन किया है।

उन्होंने कहानियां, कविताएं और बाल साहित्य रचकर डोगरी भाषा को समृद्ध किया है, जिनकी



सराहना स्थानीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। भाषा संरक्षण और साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए वे कई साहित्यिक आयोजनों, पुस्तक विमोचनों, कविता पाठ और

सम्मेलनों में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं।

यशपाल निर्मल डोगरी भाषा अकादमी, जम्मू-कश्मीर हिंदी अकादमी और नट मंच के संस्थापक भी हैं। उन्हें वर्ष 2014 में ‘मियां डीडो’ के लिए साहित्य अकादमी का राष्ट्रीय अनुवाद पुरस्कार मिला।

वर्ष 2018 में ‘छुट्टियां’ बाल उपन्यास के लिए प्यारी देवी घासी राम सिहाग बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसका अनुवाद 27 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित हो चुका है।

इसके अलावा, उन्हें 2023 में पं. हरप्रसाद पाठक बाल पुरस्कार, 2024 में बाल वाटिका पुरस्कार, 2020 में ‘1008 डोगरी हाइकू’ के लिए सिया राम सहगल पुरस्कार तथा 2023-24 में डॉ. गार्गी गुप्ता द्विवेदी पुरस्कार भी मिल चुका है।

यूजीसी के नए नियम : सुधार की मंशा और सियासी सवाल



सबका जम्मू कश्मीर

देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर बदलाव के दौर से गुजर रही है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा लागू किए गए नए नियमों और ढांचागत परिवर्तनों ने शिक्षा जगत के साथ-साथ राजनीतिक गलियारों में भी तीखी बहस छेड़ दी है। सरकार इन्हें शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, जबकि विपक्ष और कई शिक्षाविद इसे अकादमिक स्वायत्तता और संघीय व्यवस्था पर प्रहार के रूप में देख रहे हैं।

नए के हालिया सुधारों में चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली, कुलपतियों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव, फैकल्टी की भर्ती में लचीलापन तथा विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में परिसर खोलने की

अनुमति जैसे प्रावधान शामिल हैं। इनका उद्देश्य छात्रों को अधिक विकल्प देना, उच्च शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाना और शोध एवं नवाचार को प्रोत्साहित करना बताया जा रहा है। निस्संदेह, बदलते समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में सुधार आवश्यक है, किंतु सुधारों का स्वरूप और प्रक्रिया उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।

चिंता का बड़ा कारण यह है कि इन नियमों को लेकर राज्यों और विश्वविद्यालयों से व्यापक विमर्श नहीं हुआ।

शिक्षा समवर्ती विषय है, फिर भी कई राज्य सरकारों को यह महसूस हो रहा है कि केंद्र सरकार यूजीसी के माध्यम से निर्णय थोप रही है। कुलपतियों की नियुक्ति और विश्वविद्यालय प्रशासन में बढ़ते केंद्रीकरण के आरोप इस असंतोष को और गहरा करते हैं। यह स्थिति संघीय ढांचे की भावना के अनुरूप नहीं मानी जा

सकती।

शैक्षणिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और एकाधिक प्रवेश-निकास प्रणाली को लचीला बताया जा रहा है, लेकिन आशंका है कि आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर छात्र पढ़ाई अधूरी छोड़ने को विवश हो सकते हैं। इससे डिग्री की गरिमा और शिक्षा की निरंतरता पर असर पड़ सकता है। वहीं, फैकल्टी की संविदात्मक नियुक्तियों को लेकर यह चिंता जताई जा रही है कि इससे शिक्षण और शोध की गुणवत्ता प्रभावित होगी।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो नए सुधार शिक्षा से अधिक सत्ता और नियंत्रण का विषय बनते जा रहे हैं। सत्तापक्ष इन्हें “नए भारत” की जरूरत बता रहा है, जबकि विपक्ष इसे शिक्षा के व्यावसायीकरण और केंद्रीकरण की संज्ञा दे रहा है। छात्र और शिक्षक संगठनों के विरोध-प्रदर्शन इस बात का संकेत हैं कि जमीनी स्तर पर इन सुधारों को लेकर असमंजस और असंतोष बना हुआ है।

आवश्यकता इस बात की है कि शिक्षा सुधारों को राजनीतिक टकराव का विषय बनाने के बजाय व्यापक सहमति से आगे बढ़ाया जाए। नए के बदलाव तभी सार्थक होंगे, जब वे अकादमिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और संघीय संतुलन को बनाए रखते हुए लागू किए जाएं। शिक्षा का उद्देश्य केवल संरचना बदलना नहीं, बल्कि देश के भविष्य को मजबूत करना होना चाहिए।

राज कुमार (मुख्य संपादक)
सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ जिले में पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 8 थाना प्रभारियों के तबादले



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ। कठुआ जिले में पुलिस प्रशासन में बदलाव करते हुए एसएसपी मोहिता शर्मा ने 8 पुलिस इंस्पेक्टरों के तबादले किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार आशीष शर्मा को कठुआ थाना का नया एसएचओ नियुक्त किया गया है।

वहीं कठुआ थाना के संदीप चिब को पहाड़ी क्षेत्र के थाना का प्रभारी बनाया गया है।

इसी क्रम में राजबाग के अजय चिब को कठुआ साइबर थाना का एसएचओ बनाया गया है, जबकि उनकी जगह सुशील शर्मा राजबाग थाना के नए एसएचओ होंगे।

इसके अलावा हीरानगर थाना की कमान अब

अमित कुमार संभालेंगे, जबकि बसोहली थाना के नए एसएचओ के रूप में राजेश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है।

पुलिस विभाग में किए गए इन तबादलों को प्रशासनिक मजबूती और कानून-व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

सप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

लरू में 5 फरवरी को बाबा दर्शन शाह चिश्ती दरगाह पर 24वां सूफी मेला व भंडारा



सबका जम्मू कश्मीर

राम सिंह : हर साल की तरह इस वर्ष भी 5 फरवरी 2026 को बाबा दर्शन शाह चिश्ती की दरगाह पर 24वां सूफी मेला और भंडारा श्रद्धा और उत्साह के साथ आयोजित किया जा रहा है। यह मेला लरू क्षेत्र में मनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में संगत के पहुंचने की उम्मीद है।

दरगाह पर ध्वजारोहण और चाद. रपोशी की रस्म बाबा सरदारी शाह जी द्वारा अदा की जाएगी।

शाम के समय सूखी महफिल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीनानगर के सोनू एंड पार्टी के लखा साई कवाल अपनी कवालियां प्रस्तुत करेंगे।

इसके अलावा अन्य कलाकार भी अपनी प्रस्तुतियों से महफिल को सजाएंगे। मेले के दौरान गुरु का अटूट लंगर दिन-रात संगत के लिए परोसा जाएगा। मेले का आयोजन आसपास की संगत के सहयोग से किया जा रहा है। मेले से संबंधित जानकारी बाबा सरदारी शाह जी से प्राप्त हुई है।

कबीर साहिब के 508वें अंतर्ध्यान दिवस पर सद्गुरु मधुपरमहंस जी महाराज का संदेश : मन और माया से ऊपर उठने का आह्वान



सबका जम्मू कश्मीर

रॉजड़ी (जम्मू) : कबीर साहिब के 508वें अंतर्ध्यान दिवस के अवसर पर साहिब बंदगी के सद्गुरु श्री मधुपरमहंस जी महाराज ने रॉजड़ी, जम्मू में आयोजित कार्यक्रम में अपने प्रवचनों से संगत को निहाल किया। उन्होंने कहा कि तत्व ज्ञान पर अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन मन सब कुछ भुला देता है। मन का प्रभाव इतना गहरा है कि इंसान अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। सद्गुरु जी ने कहा कि क्रोध, लोभ और अहंकार आने पर मनुष्य अपनी बुद्धि खो बैठता है और गलत कार्य कर बैठता है। आज भक्ति का क्षेत्र भी व्यवसाय बन गया है और इंसान भौतिक सुखों में उलझ गया है। उन्होंने

कहा कि शरीर नश्वर है, जबकि गुरु अमृत की खान के समान है। मन की अपनी एक फौज है, जिससे हमेशा सावधान रहने की जरूरत है।

उन्होंने समझाया कि सच्चा अध्यात्म यह जानने में है कि हमारी आत्मा और मन कैसे काम करते हैं। आत्मा पवित्र और निर्मल है, लेकिन मन और माया के जाल में फँसाकर उसे भ्रमित रखा गया है। भूख और प्यास शरीर और तत्वों के कारण हैं, आत्मा इन सबसे परे है।

सद्गुरु मधुपरमहंस जी महाराज ने कहा कि जिस शरीर पर मनुष्य अहंकार करता है, वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस मृत्यु लोक से सबको जाना है, फिर भी मनुष्य सोचने को तैयार नहीं है। उन्होंने चिंता जताई कि आज कबीर पंथ में भी भ्रम फैल रहा है और साहिब कबीर की मूल शिक्षा से लोग दूर हो रहे हैं। परिवारवाद और दिखावे ने सच्चे गुरु की पहचान को कठिन बना दिया है।

उन्होंने संगत से अपील की कि वे कबीर साहिब की मूल शिक्षाओं को समझें और मन, माया व अहंकार से ऊपर उठकर आत्मज्ञान के मार्ग पर चलें।

म्यूनिसिपल कमेटी नगरी में 77वें गणतंत्र दिवस पर फहराया गया तिरंगा

सबका जम्मू कश्मीर

नगरीरू कस्बा नगरी स्थित म्यूनिसल कमेटी कार्यालय में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर तिरंगा फहराया गया। कार्यक्रम में म्यूनिसिपल कमेटी के एकजीक्यूटिव ऑफिसर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और नगरवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर एकजीक्यूटिव ऑफिसर ने लोगों से अपील की

कि वे नगरी को स्वच्छ और सुंदर बनाने में म्यूनिसिपल कमेटी का सहयोग करें, ताकि शहर को साफ-सुथरा और बेहतर बनाया जा सके।

कार्यक्रम में पूर्व अध्यक्ष तरसेम पाल सेनी, पूर्व अध्यक्ष शशिकांत वर्मा, वार्ड नंबर पांच के पार्षद सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने देश के प्रति अपनी एकजुटता और स्वच्छता के संकल्प को दोहराया

5-दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग को लेकर देशभर में बैंक हड़ताल, कामकाज ठप



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू, 5-दिवसीय कार्य सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू एफ बी यू) के आह्वान पर मंगलवार को देशभर में बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने

हड़ताल व प्रदर्शन किए। हड़ताल का व्यापक असर रहा और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों सहित कई निजी व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में कामकाज पूरी तरह बंद रहा। सभी प्रमुख शहरों और कस्बों में बैंक कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में भाग लेकर प्रदर्शन किए।

कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से बढ़ते कार्यभार, अतिरिक्त काम के घंटे और छुट्टियों में भी ख़ुट्टी के दबाव का सामना कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग बढ़ने के बावजूद छह-दिवसीय कार्य सप्ताह जारी रहना कर्मचारियों के लिए कठिन हो गया है।

एआईबीओसी नेताओं राजेश मेहता और विशाल वर्मा ने बताया कि मार्च 2024 में भारतीय बैंक संघ (आई बी ए) और यू एफ बी यू के बीच 5-दिवसीय कार्य सप्ताह पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अब तक सरकार की मंजूरी और अधिसूचना जारी नहीं हुई है। कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी निर्णय न होने से कर्मचारियों को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा।

यू एफ बी यू ने स्पष्ट किया कि हड़ताल शांतिपूर्ण और पूरी तरह संवैधानिक रही। कर्मचारियों ने कहा कि वे जनता की सेवा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि बेहतर कार्य-जीवन संतुलन और मानवीय कार्य परिस्थितियों की मांग कर रहे हैं, जिससे बैंकिंग व्यवस्था और मजबूत होगी।

यू एफ बी यू ने केंद्र सरकार से मांग की है कि बैंकों में 5-दिवसीय कार्य सप्ताह को जल्द मंजूरी देकर लागू किया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

कठुआ में खैर लकड़ी की तस्करी नाकाम

देर रात वन विभाग की कार्रवाई, वाहन सहित 15 गुट्टे जब्त



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : वन विभाग, कठुआ ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए खैर लकड़ी की तस्करी के प्रयास को नाकाम कर दिया। 27 जनवरी की रात करीब 11:55 बजे बुधी ब्लॉक के गांव रौड़ी, सहर पंचायत के पास एक टाटा योद्धा लोड कैरियर (श्रज08स-1637) को रोककर जांच की गई।

जांच के दौरान वाहन में 15 गुट्टे अवैध खैर लकड़ी पाए गए, जिन्हें बिना अनुमति के ले जाया जा रहा था। वन विभाग की टीम ने मौके पर ही वाहन को जब्त कर लिया और मामले में भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत कार्रवाई शुरू

कर दी। यह कार्रवाई रेंज अधिकारी कठुआ नीतन खजूरिया की निगरानी में तथा संभागीय वन अधिकारी अंकित सिन्हा (आईएफएस) के मार्गदर्शन में की गई। जब्त वाहन और लकड़ी को वन परिसर, कठुआ में सुरक्षित रखा गया है।

वन विभाग ने बताया कि जिले में खैर लकड़ी व अन्य वन उपज की तस्करी रोकने के लिए राजस्व विभाग, पुलिस और वन सुरक्षा बल मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अवैध कटाई या तस्करी की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि वन संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज हीरानगर में 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया



सबका जम्मू कश्मीर

हीरानगर : राजकीय जीएलडीएम डिग्री कॉलेज,

हीरानगर में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस पूरे उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के छात्र-छात्राओं, शिक्षकों

और गैर-शिक्षण कर्मचारियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज की प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा खन्ना द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने से हुई। इसके बाद राष्ट्रगान गाया गया।

इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य, कविता और भाषणों के माध्यम से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिन्हें उपस्थित लोगों ने खूब सराहा।

अपने संबोधन में प्राचार्या डॉ. प्रज्ञा खन्ना ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए संविधान के मूल्यों, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर जोर दिया।

कार्यक्रम का समापन धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। आयोजन के माध्यम से संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों को अपनाने का संदेश दिया गया।

तहसील नगरी में 77वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया



नगरी/कठुआ : सोमवार को तहसील नगरी में 77वां गणतंत्र दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर तहसीलदार नगरी ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। कार्यक्रम के दौरान स्कूली छात्र-छात्राओं द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि तहसीलदार नगरी ने उपस्थित

लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, लोकतंत्र और राष्ट्रीय मूल्यों का प्रतीक है।

उन्होंने सभी नागरिकों से संविधान के आदर्शों का पालन करने और देश की एकता व अखंडता बनाए रखने का आह्वान किया।

77वें गणतंत्र दिवस पर हिरानगर प्रशासन ने वरिष्ठ मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा को किया सम्मानित

सबका जम्मू कश्मीर

हिरानगर : 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिरानगर प्रशासन द्वारा प्रसिद्ध वरिष्ठ मूर्तिकार गणेश कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। यह भव्य समारोह हिरानगर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारी, गणमान्य अतिथि और नागरिक उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान उप जिला मजिस्ट्रेट फुलैल सिंह, तहसीलदार अनूप शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने गणेश कुमार शर्मा को मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा पिछले 45 वर्षों से जम्मू-कश्मीर की कला और संस्कृति के प्रचार-प्रसार के लिए सम्मानित किया।

गणेश कुमार शर्मा अब तक राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनेक पुरस्कार और सम्मान प्राप्त कर चुके हैं। हाल ही में उन्हें इंटरनेशनल वर्ल्ड आइकॉन अवॉर्ड 2025 से भी सम्मानित



किया गया है।

वे मूल रूप से सांबा जिले के सीमावर्ती गांव सनूरा के निवासी हैं और वर्तमान में हिरानगर में निवास कर रहे हैं।

इस अवसर पर प्रशासन और आयोजन समिति के सदस्यों ने गणेश कुमार शर्मा को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और कला के क्षेत्र में निरंतर सफलता की कामना की।

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक सदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

कठुआ ने अपने वीर सपूत शहीद कैप्टन सुनील चौधरी को दी भावभीनी श्रद्धांजलि



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : देश की सेवा में अपने प्राण न्योछावर करने वाले शहीद कैप्टन सुनील चौधरी की शहादत की वर्षगांठ पर आज कठुआ में श्रद्धा और सम्मान के साथ स्मृति कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कैप्टन सुनील चौधरी चौक, कठुआ में संपन्न हुआ, जहां प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, सेना के वरिष्ठ व कनिष्ठ अधिकारियों, शहीद के परिजनों, पूर्व

सैनिकों तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने एकत्र होकर शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर देश के इस वीर सपूत को नमन किया और उनकी वीरता को स्मरण किया।

कार्यक्रम के दौरान सेना के जवानों ने शहीद को सैन्य सम्मान के साथ सलामी दी, जिससे वातावरण देशभक्ति और गौरव की भावना से ओत-प्रोत हो गया। इस अवसर पर उपायुक्त कठुआ राजेश

शर्मा, विधायक कठुआ डॉ. भारत भूषण, एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताते हुए उनके अदम्य साहस और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की।

कार्यक्रम में शहीद के पिता कर्नल (सेवानिवृत्त) पी.एल. चौधरी ने अपने पुत्र की वीरता को याद करते हुए बताया कि कैप्टन सुनील चौधरी 27 जनवरी 2008 को असम

में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत बना रहेगा और युवाओं को देश सेवा के लिए प्रोत्साहित करता रहेगा।

प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने शहीद को कठुआ की शान बताते हुए कहा कि इस जिले ने देश को अनेक वीर सपूत दिए हैं, जिन पर पूरे क्षेत्र को गर्व है।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा क्लासीफाईड

आवश्यकता प्रॉपर्टी लोन व्यापार ज्योतिष

बुकिंग के लिए संपर्क करें

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

K2 LADIES GYM & K2 LIBRARY

GET IN SHAPE START TODAY

Workout join our gym

CONTACT NO.9541518471

AIRWAN ROAD NAGRI PAROLE KATHUA

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY

AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

A WORK OF ART

A FEAT OF ENGINEERING

PROFILE 20 YEARS WARRANTY

ACCESSORIES 10 YEARS WARRANTY

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY

AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

Address: Sherpur, Kathua (J&K) | M.: 9086038088, 9419162407

Email: jmbupvc@gmail.com